Kamal.Sandesh
kamalsandesh.org
KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-11
01-15 जून, 2025 (पाक्षिक)
₹20

ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य का प्रतीक

'140 करोड़ भारतीय विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं'

नई दिल्ली में 25 मई, 2025 को आयोजित एनडीए मुख्यमंत्री परिषद् में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 25 मई, 2025 को आयोजित एनडीए मुख्यमंत्री परिषद् के समापन पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में 18 मई, 2025 को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पवित्र स्थल 'आदि-कैलाश' का दौरा करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

गांधीनगर (गुजरात) में 18 मई, 2025 को तिरंगा यात्रा में भाग लेते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

नारनपुरा (गुजरात) में 18 मई, 2025 को विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

गुजरात में 16 मई, 2025 को भुज वायुसेना स्टेशन का दौरा कर बहादुर वायु योद्धाओं एवं सैनिकों से बातचीत करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **140 करोड़ भारतीय 'विकसित भारत' के निर्माण में एकजुट हैं: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई को गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास...

09 **'भारत अब पिछले वर्षों की तुलना में बुनियादी ढांचे के विकास में छह गुना अधिक निवेश कर रहा है'**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 मई को...

11 **'विकसित भारत' का सपना विकसित राज्यों के माध्यम से साकार हो सकता है: प्रधानमंत्री**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति...

12 **ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य का प्रतीक**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 25 मई, 2025 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय...

14 **पूर्वोत्तर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन रहा है: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट...

लेख

जीइएम पोर्टल ने भारत की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को कैसे बदला / **पीयूष गोयल** 22
ऑपरेशन सिंदूर: साहस, शक्ति और नए भारत की ललकार / **तरुण चुग** 24
एक नए बस्तर का निर्माण / **विष्णुदेव साय** 26
जाति की गणना ही समावेशी हिंदुत्व है / **गुरु प्रकाश** 28

अन्य

शहरी क्षेत्र हमारे विकास केंद्र हैं: प्रधानमंत्री 07
भारत अब निर्णायक नेतृत्व वाला देश है जो आतंकी हमलों का जवाब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से देता है: अमित शाह 15
'ऑपरेशन सिंदूर': राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भर नवीन पद्धति का उदय 16
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई को दी मंजूरी 19
अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025 के दौरान कोयला आयात में 9.2 प्रतिशत की कमी 20
'मोदी सरकार 31 मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध' 21
प्रधानमंत्री ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन (ग्लेक्स) 2025 को किया संबोधित 29
एक-एक उड़ान से भारत को जोड़ना 30
मन की बात 33
एनडीए ने असम पंचायत चुनावों में शानदार जीत हासिल की 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

ऑपरेशन सिंदूर के जज्बे को और आगे ले जाते हुए हमें 'वोकल फॉर लोकल' को दृढ़ता से अपनाना है, ताकि हमारे देश का सामर्थ्य और बढ़े।

(27 मई, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर जी के जीवनवृत्त को सालों तक दबाकर रखा गया, उनके बार में कोई चर्चा नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी लोकमाता के कृतित्व और व्यक्तित्व को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रही है।

(31 मई, 2025)

अमित शाह

मोदीजी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की एनडीए सरकार प्रदेश की समृद्ध विरासत का संवर्धन कर रही है और किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आज नांदेड की जनसभा में जनता से मिले इस अपार स्नेह के लिए हृदय से आभार।

(26 मई, 2025)

राजनाथ सिंह

पिछले एक दशक में भारत का रक्षा क्षेत्र एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 10-11 साल पहले, जहां हमारा रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपए था, वहीं आज यह 1,46,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। और इसमें 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान निजी क्षेत्र का रहा है।

(31 मई, 2025)

बी.एल. संतोष

सात दिनों में ही वह (कर्नल सोफिया कुरैशी) युवा पीढ़ी के लिए एक आइकन बन गई हैं। सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग से नहीं, बल्कि अपने जीवन एवं अपने परिवार की विरासत से भी। वडोदरा की बेटी, बेलगावी की बहू, भारत का गौरव। #ऑपरेशनसिंदूर।

(14 मई, 2025)

शिवराज सिंह चौहान

विकसित कृषि संकल्प अभियान का यही उद्देश्य है कि किसान भाई अपनी बात कहें ताकि जो शोध हों, वो किसानों की जरूरत के अनुरूप हों। इसलिए आपके पास वैज्ञानिक आ रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़ें और अपनी बात रखें ताकि खेती को विकसित बनाया जा सके।

(29 मई, 2025)

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
गंगा दशहरा (05 जून)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

विश्व से अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान

'ऑपरेशन सिंदूर' से पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को देखा। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं निर्णायक नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का पूरे देश का संकल्प और भी अधिक मजबूत हुआ है। आतंकवादी समूहों को उनके घर में ही घुसकर मारने के साथ-साथ भारत ने कड़े राजनयिक एवं आर्थिक कदम उठाए हैं। सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित करने के साथ-साथ पाकिस्तान के राजनयिकों को देश से वापस भेजा गया है तथा व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई देशों के साथ भारत ने वैश्विक कूटनीति के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि भारत की कार्रवाई न्यायसंगत, सीमित तथा आतंकवादियों पर केंद्रित थी। इससे भारत के पक्ष में वैश्विक समझ और अधिक मजबूत हुई है। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध संयम और सामर्थ्य, जो सोची समझी सैद्धांतिक प्रत्युत्तर से युक्त सटीक एवं लक्ष्यात्मक था, का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज भारत के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के संकल्प को विश्व समर्थन दे रहा है और साथ ही सराह भी रहा है।

एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने 59 सांसदों की सप्त सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर 32 देशों तथा यूरोपीय यूनियन में भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर इन प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता के प्रमाण दिए और साथ ही बताया कि भारत की सैन्य कार्रवाई यथोचित एवं आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर केंद्रित रही। साथ ही उन्होंने भारत की कार्रवाई को विधिसम्मत एवं सोच-समझकर लिए गए कदम के रूप में अंतरराष्ट्रीय जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों, सांसदों, चिंतन समूहों एवं संबंधित संस्थाओं से मिलकर भारत के पक्ष को विस्तार से प्रस्तुत किया है। इससे देश में भी विश्वास का वातावरण बना है तथा आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है, उसका संदेश पूरे विश्व में गया है। इससे जनविश्वास एवं राष्ट्रीय मनोबल और अधिक सुदृढ़ हुआ है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के साथ-साथ दूसरे देशों को विश्वास में लेने का परिपक्व राजनैतिक कौशल की भारत की संतुलित नीति को हर ओर सराहा जा रहा है।

देश द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने न केवल आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की बल्कि अपार धैर्य का प्रदर्शन किया। यह जगजाहिर है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों को समर्थन, प्रशिक्षण, हर प्रकार का सहयोग तथा दूसरे देशों में उन्हें भेजने का लंबा इतिहास रहा है। इसके बाद भी भारत ने असीम संयम का परिचय दिया है। फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका एवं यूएई जैसे देशों ने भारत के पक्ष को समझते हुए सहयोगपूर्ण वक्तव्य दिए हैं। किसी भी बड़े देश ने भारत के पक्ष से असहमति व्यक्त नहीं की है, जिससे भारत द्वारा भेजे गए संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की प्रभावशीलता का पता चलता है। त्रिनिडाड एवं टाबैगो, फिजी एवं गुयाना जैसे देशों में जहां बड़ी संख्या में भारतवंशी रहते हैं, ने खुलकर भारत के पक्ष का समर्थन किया है तथा मोदी सरकार के सक्रिय रूप से सभी देशों से संवाद स्थापित करने के प्रयास को सराहा है। खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकियों के प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता को रोकने के इन देशों के साथ मजबूत आतंकवाद विरोधी सहयोग एवं समझ का निर्माण हुआ है। पाकिस्तान द्वारा इस विषय के अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रयास पूरी तरह से विफल हुए, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ नापाक गठजोड़ से पूरा विश्व अवगत है। इन कूटनीतिक प्रयासों से जहां पूरे विश्व में भारत के आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई को समर्थन मिला है, वहीं पाकिस्तान अलग-थलग पड़ चुका है।

> **भारत ने अपनी संप्रभुता को दृढ़तापूर्वक अक्षुण्ण रखते हुए आतंकवाद के विरुद्ध अपने गैर-समझौतावादी एवं अटल सिद्धांत से पुनः पूरे विश्व को परिचित कराया है**

'ऑपरेशन सिंदूर' से एक 'न्यूनॉर्मल' स्थापित हुआ है। अब भारत आतंकवाद के विरुद्ध बिना पाकिस्तान से युद्ध घोषित किए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान का परमाणु ब्लैकमेल अब भारतीय सैन्य कार्रवाई को रोक नहीं सकता। इन प्रतिनिधिमंडलों ने सफलतापूर्वक भारत के इस सिद्धांत को सुदृढ़ किया है तथा यह प्रमाणित किया है कि भारत यदि निर्णायक रूप से कदम बढ़ाए, तब विश्व अभिमत को कूटनीतिक तरीके से बिना अलग-थलग पड़े, विश्वसनीयता के साथ अपने पक्ष में मोड़ सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि टेरर, टॉक और ट्रेड न एक साथ चल सकता है, न ही पानी और खून एक साथ बह सकता है। वास्तव में, भारत ने अपनी संप्रभुता को दृढ़तापूर्वक अक्षुण्ण रखते हुए आतंकवाद के विरुद्ध अपने गैर-समझौतावादी एवं अटल सिद्धांत से पुनः पूरे विश्व को परिचित कराया है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

140 करोड़ भारतीय 'विकसित भारत' के निर्माण में एकजुट हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई को गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 26 मई का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने गुजरात के लोगों के अटूट समर्थन और आशीर्वाद को स्वीकार किया, जिन्होंने उन्हें देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस विश्वास और प्रोत्साहन ने दिन-रात देश की सेवा के लिए उनके समर्पण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा, "आज देश निराशा और अंधकार के युग से निकलकर आत्मविश्वास और आशावाद के नए युग में प्रवेश कर चुका है।"

श्री मोदी ने कहा, "140 करोड़ भारतीय एक विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं।" उन्होंने भारत के भीतर आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता समय की मांग है। श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत अब स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, खिलौने, रक्षा उपकरण और दवाओं सहित कई तरह के उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत न केवल रेल और मेट्रो तकनीक का विनिर्माण कर रहा है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर निर्यात भी कर रहा है। इस प्रगति का एक प्रमुख उदाहरण दाहोद, जहां हजारों करोड़ रुपये की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया, को बताते हुए श्री मोदी ने दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया।

उन्होंने तीन वर्ष पूर्व इसकी आधारशिला रखने को याद किया और गर्वपूर्वक कहा कि अब पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सफलतापूर्वक विनिर्मित किया गया है। उन्होंने लोकोमोटिव को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गुजरात और पूरे देश के लिए गौरव का क्षण था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि गुजरात ने अपने रेलवे नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया है।

लगभग 70 रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें

पिछले 10-11 वर्षों में भारत के रेलवे क्षेत्र के त्वरित विकास को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने मेट्रो सेवाओं के विस्तार और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत पर जोर दिया, जिससे पूरे देश में कनेक्टिविटी रूपांतरित हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें अब लगभग 70 रूटों पर चल रही हैं, जो भारत के परिवहन नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाती हैं। उन्होंने अहमदाबाद और वेरावल के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की घोषणा की।

श्री मोदी ने रेखांकित किया कि गुजरात ने शिक्षा, आईटी, सेमीकंडक्टर और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसने खुद को विभिन्न उद्योगों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में हजारों करोड़ रुपये के निवेश से एक प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि ये पहल गुजरात में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान दे रही हैं।

इस बात को रेखांकित करते हुए कि दाहोद, वडोदरा, गोधरा, कलोल और हलोल ने सामूहिक रूप से गुजरात में एक उच्च तकनीक इंजीनियरिंग और विनिर्माण गलियारा स्थापित किया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वडोदरा विमान विनिर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कुछ ही महीने पहले एयरबस असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया है।

प्रधानमंत्री ने पिछले 20 वर्ष के दौरान गुजरात के शहरी विकास पर केंद्रित समारोह को किया संबोधित

शहरी क्षेत्र हमारे विकास केंद्र हैं: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 मई को गुजरात के गांधीनगर में पिछले 20 वर्षों के दौरान गुजरात शहरी विकास पर केंद्रित समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने शहरी विकास वर्ष 2005 के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दो दिनों में वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गर्जना और तिरंगे को फहराते हुए देशभक्ति के जोश का अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि यह देखने लायक दृश्य था और यह भावना केवल गुजरात में ही नहीं, बल्कि भारत के हर कोने में और हर भारतीय के दिल में थी। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है और इसे पूरी दृढ़ता के साथ पूरा किया।"

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा शांति और स्थिरता की वकालत की है, लेकिन इसकी ताकत को बार-बार चुनौती दिए जाने के कारण सख्त जवाब की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, जिसे छद्म युद्ध कहा जाता था, खासकर 6 मई की घटनाओं के बाद वह अब बदल गया है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए इस तरह के कृत्यों को छद्म युद्ध कहना एक गलती होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि 22 मिनट के भीतर नौ पहचाने गए आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें कैमरा डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई, ताकि घरेलू स्तर पर किसी भी सबूत पर सवाल न उठाया जा सके। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाल की घटनाएं साबित करती हैं कि यह अब महज छद्म युद्ध नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक सोची-समझी

और सुनियोजित सैन्य रणनीति है।

श्री मोदी ने शहरी विकास के प्रति गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य ने 2005 में इस पहल की शुरुआत की थी और अब यह दो दशकों की प्रगति का जश्न मना रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केवल उपलब्धियों का जश्न मनाने के बजाय सरकार ने पिछले 20 वर्षों से अपने अनुभवों का उपयोग शहरी विकास को लेकर अगली पीढ़ी के लिए अनुकूल भविष्य-केंद्रित रोडमैप बनाने के लिए किया है।

शहरी केंद्रों को जनसंख्या वृद्धि के कारण विस्तार करने के बजाय आर्थिक विकास के केंद्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा, "शहरों को आर्थिक गतिविधि के लिए सशक्त केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और नगर निकायों को उनके परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से योजना बनानी चाहिए।" उन्होंने देश भर के नगर निगम और महानगरीय अधिकारियों से अपने-अपने शहरों के लिए आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया।

ज्यादातर टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं लगभग दो लाख स्टार्टअप

श्री मोदी ने कहा कि जबकि बड़े उद्योग पारंपरिक रूप से महानगरीय क्षेत्रों के आसपास पनपते थे, ज्यादातर टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित लगभग दो लाख स्टार्टअप का उदय होना एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने गर्व के साथ स्वीकार किया कि इनमें से कई उपक्रमों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जो आर्थिक और उद्यमशीलता की क्रांति की एक नई लहर का संकेत है।

प्रधानमंत्री ने गुजरात के बदलाव का उदाहरण देते हुए आर्थिक विकास को गति देने में पर्यटन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कच्छ, जो कभी अपने रेगिस्तानी परिदृश्य के कारण अनदेखा किया जाता था, अब एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है। श्री मोदी ने बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जैसी बड़े पैमाने की पहल ने धारणाओं को नया आकार दिया है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है। ■

आज कच्छ व्यापार और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई को गुजरात के भुज में 53,400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कच्छ के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और विशेष रूप से महान स्वतंत्रता सेनानी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा सहित क्रांतिकारियों और शहीदों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने उनके लचीलेपन एवं योगदान को स्वीकार करते हुए कच्छ के बेटों और बेटियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। कच्छ के साथ अपने गहरे संबंध को प्रकट करते हुए श्री मोदी ने जिले भर में अपनी लगातार यात्राओं को याद किया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे इस भूमि ने उनके जीवन की दिशा को आकार दिया है।

50,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज कच्छ व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में खड़ा है।" उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की भूमिका और भी बड़ी होगी। श्री मोदी ने कच्छ के तेज विकास को देखने और इसकी प्रगति का समर्थन करने पर अपनी खुशी व्यक्त की। अपनी यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल भारत के एक प्रमुख नीली अर्थव्यवस्था और हरित ऊर्जा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

श्री मोदी ने हरित हाइड्रोजन की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हुए इसे भविष्य का ईंधन बताया और कहा, "कच्छ दुनिया में हरित ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है।" उन्होंने कहा कि कार, बस और स्ट्रीट लाइट जल्द ही हरित हाइड्रोजन से संचालित होंगी, जिससे भारत के ऊर्जा परिदृश्य में क्रांति आएगी। श्री मोदी ने कहा कि कांडला देश के तीन नामित हरित हाइड्रोजन केंद्रों में से एक है। उन्होंने कच्छ में एक नए हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखने की घोषणा की और जोर देकर कहा कि इस संयंत्र में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पूरी तरह से 'मेड इन इंडिया' है।

इसके अलावा, श्री मोदी ने भारत की सौर क्रांति में कच्छ की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि खावड़ा परिसर की स्थापना के साथ कच्छ ने वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया है।

श्री मोदी ने कच्छ कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधनी कपड़े और चमड़े के काम जैसे कच्छ के पारंपरिक शिल्प की व्यापक मान्यता पर टिप्पणी की और हथकरघा कला के एक जीवंत संग्रहालय के रूप में भुजोडी गांव की प्रशंसा की। साथ ही, उन्होंने अजरख छपाई की अनूठी परंपरा को स्वीकार किया, जिसने अब भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग हासिल कर लिया है, जिससे आधिकारिक तौर पर कच्छ में इसकी उत्पत्ति की पुष्टि होती है।

ऑपरेशन सिंदूर पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को रेखांकित करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास का उसी भाषा में कड़ा जवाब दिया जाएगा और जोर देकर कहा कि जो लोग भारत को चुनौती देने की हिम्मत करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। श्री मोदी ने टिप्पणी की कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि वह सटीकता के साथ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर सकता है। ■

'भारत अब पिछले वर्षों की तुलना में बुनियादी ढांचे के विकास में छह गुना अधिक निवेश कर रहा है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 मई को राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करने के साथ-साथ इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया और ऑनलाइन शामिल हुए 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी के प्रति भी आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए देश भर से जुड़े सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों और नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दीं।

श्री मोदी ने कहा कि वे करणी माता का आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम में आए हैं। उन्होंने कहा कि ये आशीर्वाद विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करते हैं। 26,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का उल्लेख करते हुए उन्होंने देश के विकास को आगे बढ़ाने में इनके महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने इन परिवर्तनकारी पहलों के लिए नागरिकों को बधाई दी।

भारत के बुनियादी ढांचे में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए, आधुनिकीकरण के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे और रेलवे स्टेशनों में हुई तीव्र प्रगति की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब पिछले वर्षों की तुलना में बुनियादी ढांचे के विकास में छह गुना अधिक निवेश कर रहा है, एक ऐसी प्रगति जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने देश भर में प्रतिष्ठित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की चर्चा करते हुए चिनाब ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग और पूर्व में असम में बोगीबील ब्रिज का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने पश्चिमी भारत में मुंबई में अटल सेतु का उल्लेख किया जबकि दक्षिण में उन्होंने भारत के अपनी तरह के पहले पंबन ब्रिज की चर्चा की।

34,000 किलोमीटर से अधिक नई रेलवे पटरियां

श्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की प्रगति की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें सैकड़ों सड़क ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण के साथ ही 34,000 किलोमीटर से अधिक नई रेलवे पटरियां बिछाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रॉड गेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कार्गो परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए समर्पित माल गलियारों के तेजी से विकास और भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के वर्तमान में जारी निर्माण का भी उल्लेख किया। इन प्रयासों के साथ-साथ, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक रेलवे स्टेशनों का नाम अमृत भारत स्टेशन रखा गया है और ऐसे 100 से अधिक स्टेशनों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इन स्टेशनों के अद्भुत परिवर्तन को देखा है, जो स्थानीय कला और इतिहास के प्रदर्शन के रूप में कार्य करते हैं।

बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश न केवल विकास को गति देता है बल्कि रोजगार के अवसरों का सृजन भी करता है और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देता हैं, इस बिंदु पर चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खर्च किए जा रहे हजारों करोड़ रुपये सीधे तौर पर

श्रमिकों, दुकानदारों, कारखाने के कर्मचारियों और ट्रक एवं टेम्पो ऑपरेटरों जैसे परिवहन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि एक बार बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो जाने के बाद लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। किसान अपनी उपज को कम लागत पर बाजारों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे बर्बादी कम होती है। अच्छी तरह से विकसित सड़कें और विस्तारित रेलवे नेटवर्क नए उद्योगों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को काफी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च से अंततः हर घर को लाभ होता है, जिसमें युवा लोग उभरते आर्थिक अवसरों से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं।

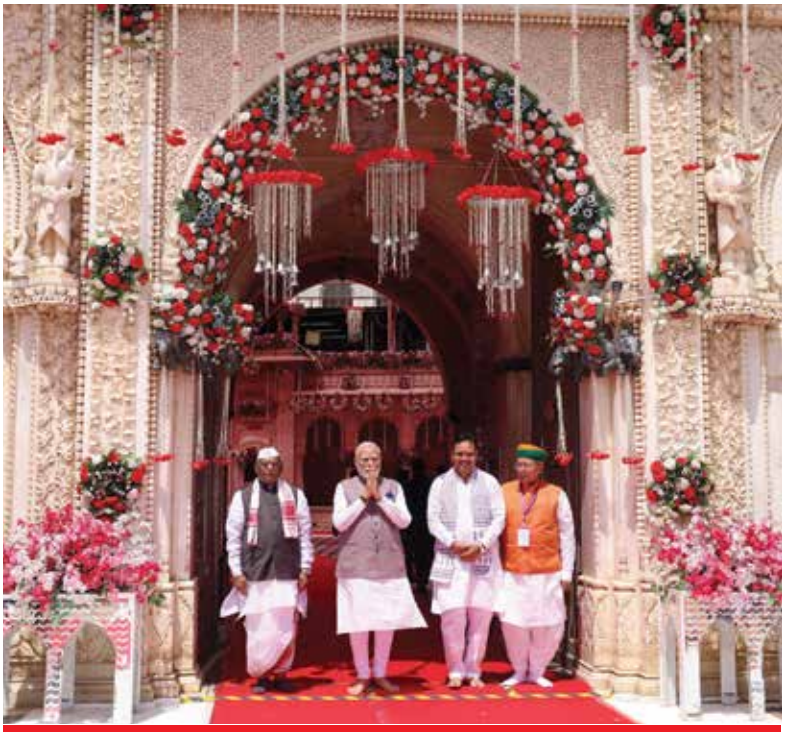

राजस्थान स्थित बीकानेर में 22 मई, 2025 को करणी माता मंदिर में दर्शन एवं पूजा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व अन्य वरिष्ठ नेतागण

पिछले 11 वर्षों में अकेले राजस्थान के सड़क बुनियादी ढांचे में लगभग 70,000 करोड़ रुपये का निवेश

श्री मोदी ने राजस्थान में जारी बुनियादी ढांचे के विकास से होने वाले लाभों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि गांवों और यहां तक कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्तायुक्त सड़कें बनाई जा रही हैं। पिछले 11 वर्षों में अकेले राजस्थान के सड़क बुनियादी ढांचे में लगभग 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार इस वर्ष राज्य में रेलवे विकास पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है, जो 2014 से पहले के स्तर की तुलना में 15 गुना वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने बीकानेर को मुंबई से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि इससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कई क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य, जल और बिजली परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास पर बल दिया।

श्री मोदी ने राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना की त्वरित प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में 40,000 से ज़्यादा लोग इस पहल से लाभान्वित हो चुके हैं, जिससे उनके बिजली बिल खत्म हो गए हैं और उन्हें सौर ऊर्जा के माध्यम से आय अर्जित करने का अवसर मिला है। उन्होंने बिजली से जुड़ी कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर चर्चा करते हुए कहा कि इन विकास कार्यों से राजस्थान की बिजली आपूर्ति में और वृद्धि होगी।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ नदियों को जोड़ने की पहल को लागू करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के प्रभाव को रेखांकित किया, जिससे राजस्थान के कई जिलों को लाभ होगा, किसानों के लिए बेहतर कृषि संभावनाएं सुनिश्चित होंगी और क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी।

राजस्थान की अटूट भावना पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश और उसके लोगों से बड़ा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की, जिसमें हमलावरों ने अपनी आस्था के आधार पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में गोलियां चलाई गईं, लेकिन उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के दिलों को घायल कर दिया, जिससे आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र का संकल्प एकजुट हुआ।

मैं देश नहीं झुकने दूंगा

श्री मोदी ने चुरू में दिए अपने बयान को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, "इस मिट्टी की सौगंध, मैं देश को गिरने नहीं दूंगा, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा।" उन्होंने राजस्थान से घोषणा की कि पवित्र सिंदूर को मिटाने का प्रयास करने वालों को धूल में मिला दिया गया है और जिन्होंने भारत का खून बहाया है, उन्हें अब इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग मानते थे कि भारत चुप रहेगा, वे अब छिप गए हैं, जबकि जो लोग अपने हथियारों के बारे में शेखी बघारते थे, वे अब मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। ■

प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की

'विकसित भारत' का सपना विकसित राज्यों के माध्यम से साकार हो सकता है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें 24 राज्यों और 7 केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने भाग लिया। इस वर्ष का विषय था विकसित भारत@2047 के लिए विकसित राज्य। बैठक की शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की याद में एक मिनट के मौन के साथ हुई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय की आकांक्षा है कि देश विकसित भारत बने। यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा है। उन्होंने कहा कि यदि सभी राज्य इस लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें तो हम शानदार प्रगति करेंगे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हर राज्य, हर शहर, हर गांव का विकास किया जाएगा और फिर 2047 से बहुत पहले 'विकसित भारत' हासिल कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को इस बदलाव की गति को बढ़ाने की जरूरत है। श्री मोदी ने राज्यों को अपनी विनिर्माण शक्तियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने विनिर्माण मिशन की घोषणा की है।

वैश्विक निवेशक भारत में काफी रुचि रखते हैं

श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक निवेशक भारत में काफी रुचि रखते हैं। उन्होंने राज्यों को इस अवसर का उपयोग करने और निवेश के लिए इसे आसान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यूएई, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौतों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को इसका अधिकतम उपयोग करना चाहिए।

कौशल विकास पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि एनईपी में शिक्षा और कौशल पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को विभिन्न कौशलों के लिए योजना बनानी चाहिए जो एआई, सेमीकंडक्टर, 3डी प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण दुनिया की कौशल राजधानी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।

श्री मोदी ने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन ने भारत को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने में मदद की है, लेकिन राज्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से वैश्विक मानकों और अपेक्षाओं के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में ऐसे 25-30 पर्यटन स्थल बनाए जा सकते हैं।

भारत में तेजी से शहरीकरण

श्री मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। उन्होंने राज्यों से शहरों को स्थिरता और विकास का इंजन बनाने को कहा और उनसे टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नये उद्यम की स्थापना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष बनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने भारत की नारी शक्ति की विशाल ताकत पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए कानून बदलने का आग्रह किया, ताकि वे विकास की राह पर चल सकें। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सुधार होने चाहिए, जिसमें उनके काम करने की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि कृषि में हमें प्रयोगशाला से लेकर जमीन तक पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में बात की जिसमें आने वाले दिनों में लगभग 2,500 वैज्ञानिक गांवों और ग्रामीण केन्द्रों में जाएंगे और वे फसल विविधीकरण और रसायन मुक्त खेती जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से इस प्रयास का समर्थन करने को कहा। ■

ऑपरेशन सिंदूर
भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य का प्रतीक

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 25 मई, 2025 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप-मुख्यमंत्रियों की बैठक के समापन के पश्चात् मीडिया को संबोधित किया और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर एवं जातिगत जनगणना पर पारित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए बैठक के अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।

ऑपरेशन सिंदूर एवं जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव पारित

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम के उद्घोष 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने जिस प्रकार देश की सेवा की, उसकी सर्वत्र सराहना हुई। इस संदर्भ में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रहे कार्यों की चर्चा की गई है। जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया और वहां सटीकता एवं मारक क्षमता के साथ हमला किया, उस पर भी इस प्रस्ताव में विस्तृत चर्चा की गई है।

उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को भारत की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है। यह भाजपा की शुरू से कल्पना रही है और बिहार सरकार, विशेष रूप से श्री नीतीश कुमार की सरकार ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा था। उसी को आधार बनाकर यह प्रस्ताव पारित हुआ। सभी लोगों ने इस निर्णय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को साधुवाद दिया। इस प्रस्ताव के माध्यम से एनडीए सरकार ने यह संदेश दिया है कि एनडीए जातिगत राजनीति नहीं करती लेकिन एनडीए का उद्देश्य है कि वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और वे सभी लोग जो अब तक मुख्यधारा से वंचित रहे हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जाए।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रस्तुत किया और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने उसका अनुमोदन किया। इसे सभी एनडीए के दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया। उसी प्रकार जातिगत जनगणना से संबंधित प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्तुत किया और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण ने इसका अनुमोदन किया।

प्रधानमंत्री ने एनडीए मुख्यमंत्री परिषद् की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीए मुख्यमंत्री परिषद् की अध्यक्षता की। उन्होंने विकास की गति को बढ़ाने और डबल इंजन वाली सरकार के लाभों को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखाः "दिल्ली में एनडीए मुख्यमंत्री परिषद् में भाग लिया। हमने विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया। विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, खेल और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सर्वोत्तम पहलों के बारे में जानकारी दी। इन अनुभवों को सुनना अद्भुत था।"

"मैंने हमारी विकास यात्रा को गति देने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि डबल इंजन वाली सरकार का लाभ जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचे। स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य सेवा, युवा सशक्तीकरण, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत तालमेल बनाने के बारे में बात हुई।"

राज्यशः चर्चा

श्री नड्डा ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को तीव्र गति से विकास की ओर ले जाना है और उसे सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाना है। इस चर्चा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उनकी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ किस प्रकार प्रभावी लड़ाई लड़ी है और किस प्रकार उन्हें उसमें सफलता प्राप्त हो रही है। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के प्रयास जारी हैं और लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने इस संबंध में सरकार की रणनीति के बारे में बताया, मार्गदर्शन किया और सभी मुख्यमंत्रियों व उप-मुख्यमंत्रियों को अवगत कराया कि किस तरह इस समस्या का समाधान किया गया।

उन्होंने कहा कि एनडीए ने कुल सात बेस्ट प्रैक्टिसेज़ पर विशेष रूप से ध्यान दिया। उदाहरणस्वरूप, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आयोजित ओलंपिक्स का उल्लेख किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार बस्तर के आदिवासी लोगों की संस्कृति, खेल, खान-पान, साहित्य और कल्चर को समेटते हुए यह आयोजन हुआ। इस आयोजन में इन सभी पहलुओं का प्रतियोगितात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने कहा कि बैठक बिहार के सूखे क्षेत्रों में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों पर भी चर्चा की गई। बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने जल जीवन हरियाली परियोजना और अभियान के बारे में विस्तार से बताया। बाल विवाह के खिलाफ असम में हुई कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। इस विषय पर असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी बात रखी। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि इस क्षेत्र में जो अच्छे परिणाम मिले हैं, उन पर अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन होना चाहिए, जो वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करे। गुजरात में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की सफलता को भी सराहा गया। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस योजना के तहत आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही मुफ्त बिजली और उससे होने वाली आय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि 'हम एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार हैं।' इसी संदर्भ में, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा ने सीएम कनेक्ट कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के तहत दूर-दराज और फैले हुए इलाकों में प्रशासन को कैसे अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इस पर एक मूवी भी दिखाई गई।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विस्तृत प्रस्तुति दी। महाराष्ट्र द्वारा प्रशासनिक सुधारों के लिए किये गए प्रयासों पर भी प्रस्तुति हुई। सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य से कुछ प्रतिनिधि चुने जाएं, जो महाराष्ट्र के अनुभव का अध्ययन करें और अपने-अपने राज्यों में उसे लागू करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस परियोजना के माध्यम से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और +2 कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सैचुरेशन पॉइंट तक लाने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य उच्च और माध्यमिक शिक्षा के लिए अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का उद्बोधन भी सभी को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन बेस्ट प्रैक्टिसेज़ पर आपस में चर्चा हुई है, उन पर अध्ययन हेतु स्टडी ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए, ताकि हर राज्य इन्हें अपने यहां लागू कर सके। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह केवल सरकार की पहल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे एक जन आंदोलन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। सभी नागरिकों की इसमें सहभागिता आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण पर जोर

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ज़ोर देते हुए कहा कि अमृत सरोवर बनाए गए हैं, उनकी निगरानी और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को विशेष चिंता करनी चाहिए। यह केवल एक वन-टाइम एफर्ट नहीं है, बल्कि इनका प्रभावी उपयोग और रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी सुझाव दिया कि इन जल स्रोतों से वाटर रिचार्ज कितना हुआ, इसकी भी स्टडी की जानी चाहिए। साथ ही, हमारे पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं और बावड़ियां, उनकी सफाई और पुनर्जीवन को एक अभियान के रूप में लिया जाना चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन का निरंतर हिस्सा होना चाहिए, यह कोई 10 या 15 दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे हम सभी को जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी आह्वान किया कि 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी राज्य सरकारें न्यूनतम और नवीनतम कार्यक्रमों की योजना बनाएं, जो प्रदेश में पर्यावरण के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएं।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 9 जून को इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे यह सोचें कि 11वें वर्ष को कैसे मनाया जाए, कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और किस प्रकार भारत ने इन 11 वर्षों में विकास की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है, इन बातों को जनता के सामने कैसे रखा जाए, इस पर सभी राज्य सरकारें विचार करें।

उन्होंने कहा कि देश की जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होगी। इस पर एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए एक छोटी समिति बनाई जाएगी, जो इस विषय पर चर्चा करेगी। पहले 5 जून को पर्यावरण दिवस, फिर 9 जून को एनडीए सरकार बनने के 11 वर्ष पूर्ण होंगे और 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाएगा, जो अब अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 2015 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। इस 10वें वर्ष के उपलक्ष्य में एनडीए का एक छोटा समूह मिलकर कार्यक्रम तय करेगा। यह कार्यक्रम किसी एक सरकार का नहीं, बल्कि समाज, देश और पूरी दुनिया का कार्यक्रम है। इसे कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही 25-26 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। एनडीए इस अवसर पर जनता को यह भी बताएगा कि किन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोंटने, लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया था। 25 जून को यह 50 साल पूरे हो जाएंगे और इस विषय को भी जनता के सामने लाया जाएगा।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल कहा था कि हमें टीम इंडिया के रूप में काम करना है। उसी भावना के साथ एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और सामंजस्य के साथ एकजुट होकर इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। ■

पूर्वोत्तर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन रहा है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के भविष्य पर गर्व, उत्साह और अपार विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने भारत मंडपम में हाल ही में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव का स्मरण करते हुए इस बात पर बल दिया कि आज का कार्यक्रम पूर्वोत्तर में निवेश का उत्सव है।

श्री मोदी ने दुनिया के सबसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर हमारे विविधतापूर्ण राष्ट्र का सबसे विविध क्षेत्र है। उन्होंने व्यापार, परंपरा, वस्त्र और पर्यटन में व्याप्त संभावनाओं पर बल देते हुए कहा कि इस क्षेत्र की विविधता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है।

'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए श्री मोदी ने पूर्वोत्तर को इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक बताया। प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में हुए परिवर्तनकारी बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रगति केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिख रही है।

श्री मोदी ने पूर्वोत्तर में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की गई 700 से अधिक यात्राओं को रेखांकित किया, जो इस भूमि को समझने, लोगों की आंखों में दिखने वाली आकांक्षाओं को महसूस करने और उस विश्वास को विकास नीतियों में बदलने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पूर्वोत्तर: पिछले दशक में 11,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण

श्री मोदी ने पिछले दशक में 11,000 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण, व्यापक नई रेलवे लाइनों, हवाई अड्डों की संख्या में दोगुनी वृद्धि, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर जलमार्गों के विकास और सैकड़ों मोबाइल टावरों की स्थापना सहित प्रमुख प्रगति का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आसियान के साथ भारत का व्यापार वर्तमान में लगभग 125 बिलियन डॉलर है और आने वाले वर्षों में इसके 200 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है, जिससे पूर्वोत्तर एक रणनीतिक व्यापार सेतु और आसियान बाजारों के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर एक समय नाकाबंदी और संघर्ष से जूझ रहा था, जिसने यहां के युवाओं के अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उन्होंने शांति समझौतों के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में 10,000 से अधिक युवाओं ने शांति को अपनाने के लिए हथियार छोड़ दिए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर के शिक्षा क्षेत्र में 21,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। उन्होंने 800 से अधिक नए स्कूलों, क्षेत्र के पहले एम्स, नौ नए मेडिकल कॉलेजों और दो नए आईआईआईटी की स्थापना सहित प्रमुख विकासों का उल्लेख किया।

श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर दो रणनीतिक क्षेत्रों— ऊर्जा और सेमीकंडक्टर के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जलविद्युत और सौर ऊर्जा में सरकार के व्यापक निवेश का उल्लेख किया जिसमें कई हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं। श्री मोदी ने घोषणा की कि पूर्वोत्तर स्थित सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप जल्द ही पेश की जाएगी, जो इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है।

इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, मणिपुर के राज्यपाल श्री अजय कुमार भल्ला, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के संगमा, मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार भी उपस्थित थे। ■

भारत अब निर्णायक नेतृत्व वाला देश है जो आतंकी हमलों का जवाब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से देता है: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 26 मई, 2025 को महाराष्ट्र के नांदेड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख किया और बताया कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि निर्णायक नेतृत्व वाला देश है जो आतंकी हमलों का जवाब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से देता है। श्री शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' की भी जानकारी देते हुए 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री अतुल सावे, प्रदेश अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर बावनकुले, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री रवींद्र चव्हाण सहित अन्य नेतागण मंच पर उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि कुछ दिन पूर्व 22 तारीख को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की चुन-चुनकर निर्मम हत्या की। इस कायराना हमले के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार की जनसभा से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि 'आतंकी चाहे जहां भी छिपे हों, उन्हें ढूंढ-ढूंढकर मिट्टी में मिलाया जाएगा।' पाकिस्तान यह भूल गया था कि अब वह भारत नहीं रहा, जहां कांग्रेस की कमजोर सरकारें हुआ करती थीं। पिछले 11 वर्षों से देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब उरी में आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से उसका उत्तर दिया गया, पुलवामा में हुए आतंकी हमले का उत्तर 'एयर स्ट्राइक' से दिया गया। अब जब पहलगाम में कायराना हमला हुआ तो भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत सैकड़ों आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया।

> **जब उरी में आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से उसका उत्तर दिया गया, पुलवामा में हुए आतंकी हमले का उत्तर 'एयर स्ट्राइक' से दिया गया। अब जब पहलगाम में कायराना हमला हुआ तो भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत सैकड़ों आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया**

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत की सेना, जनता और सीमाओं से टकराने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला होगा, तो उसका जवाब गोली से नहीं बल्कि गोले से दिया जाएगा। 7 मई को रात्रि 1 बजकर 4 मिनट पर हमारी सेना ने 22 मिनट में नौ आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। 8 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारी वायु सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी कि एक भी मिसाइल या ड्रोन भारतीय जमीन को छू तक नहीं सका। 9 मई को भारतीय सेना ने उन हवाई अड्डों और एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जहां से पाकिस्तान ने हमला किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अभियान को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम देकर यह संदेश दिया है कि भारत की बहनों-बेटियों के माथे का सिंदूर सस्ता नहीं है। यदि कोई उसे मिटाने का प्रयास करेगा, तो उसे खून से जवाब मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी समय एक और अभियान 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' भी सक्रिय था, जो भारत की रणनीतिक क्षमता और संकल्प का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित नक्सलवादियों के अड्डों को सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया है। इस अभियान में पहले 27 और फिर 31 नक्सली मारे गए, जिसके बाद अब तक कुल 36 और नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और कई गिरफ्तार भी हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वह सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया है जो कभी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 'ट्रेड और टेरर' एक साथ नहीं चल सकते।

श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार महाराष्ट्र को पुनः देश का नंबर एक राज्य बनाने की दिशा में कार्य करेगी। ■

'ऑपरेशन सिंदूर'

राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भर नवीन पद्धति का उदय

भारत की बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता

वित्त वर्ष 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 से 34 गुना वृद्धि है

'ऑपरेशन सिंदूर' विषम युद्ध (सैन्यकर्मियों के साथ-साथ निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाना) के उभरते स्वरूप के लिए एक संतुलित सैन्य प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। अप्रैल, 2025 में पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमला इसी स्वरूप की याद दिलाता है। इसके बाद भारत की प्रतिक्रिया सतर्क, सटीक और रणनीतिक थी। नियंत्रण रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना भारतीय सेना ने आतंकवादी ढांचे पर हमला कर कई खतरों को खत्म कर दिया। हालांकि, सामरिक प्रतिभा के अलावा इसमें सबसे खास बात स्वदेशी हाई-टेक प्रणालियों का राष्ट्रीय रक्षा में निर्बाध एकीकरण थी। चाहे ड्रोन युद्ध हो, बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा हो या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध 'ऑपरेशन सिंदूर' सैन्य अभियानों में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

हवाई सुरक्षा क्षमताएं: सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में तकनीक

07-08 मई, 2025 की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें एकीकृत काउंटर यूएएस (मानव रहित हवाई प्रणाली) ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया।

हवाई सुरक्षा प्रणालियां रडार, नियंत्रण केंद्रों, तोपखाने और विमान और जमीन-आधारित मिसाइलों के नेटवर्क का उपयोग करके ऐसे खतरों का पता लगाकर उनका पीछा करते हुए उन्हें बेअसर करती हैं।

8 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर हवाई सुरक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। लाहौर में एक हवाई सुरक्षा प्रणाली को बेअसर कर दिया गया।

प्रणालियों का प्रदर्शन

'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत निम्नलिखित का उपयोग किया गया:

- युद्ध-प्रमाणित एडी (वायु रक्षा) प्रणालियां जैसे पिकोरा, ओएसए-एके और एलएलएडी गन (निम्न-स्तरीय वायु रक्षा बंदूकें)।

बेहतर प्रदर्शन करने वाली आकाश जैसी स्वदेशी प्रणालियां

> भारत के आक्रामक हमलों ने सर्जिकल सटीकता के साथ प्रमुख पाकिस्तानी एयरबेस— नूर खान और रहीमयार खान को निशाना बनाया। विनाशकारी प्रभाव के लिए लोइटरिंग हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से प्रत्येक ने दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम सहित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ढूंढा और नष्ट किया

आकाश छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है जो हवाई हमलों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों और सामरिक बिंदुओं की रक्षा करती है। आकाश हथियार प्रणाली समूह मोड या स्वायत्त मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मेजर (ईसीसीएम) सुविधाएं अंतर्निहित हैं। संपूर्ण हथियार प्रणाली को मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर विशिष्ट कार्यों के अनुरूप किया गया है।

भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली ने सेना, नौसेना और मुख्य रूप से वायु सेना की युद्धक सामग्रियों को मिलाकर असाधारण तालमेल के साथ प्रदर्शन किया है। इन प्रणालियों ने एक अभेद्य दीवार बनाई, जिसने पाकिस्तान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई के कई प्रयासों को विफल कर दिया।

भारतीय वायुसेना की एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस) इन सभी घटकों को एक साथ लाई, जिससे आधुनिक युद्ध के लिए आवश्यक केंद्रित परिचालन क्षमता प्रदान की गई।

अत्यधिक सटीकता के साथ आक्रामक कार्रवाई

भारत के आक्रामक हमलों ने सर्जिकल सटीकता के साथ प्रमुख पाकिस्तानी एयरबेस— नूर खान और रहीमयार खान को निशाना बनाया। विनाशकारी प्रभाव के लिए लोइटरिंग हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से प्रत्येक ने दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम सहित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ढूंढा और नष्ट किया।

लोइटरिंग हथियारों को 'आत्मघाती ड्रोन' या 'कामिकेज ड्रोन' के रूप में भी जाना जाता है, वे ऐसी हथियार प्रणालियां हैं जो हमला करने से पहले उपयुक्त लक्ष्य की तलाश में अपने लक्ष्य क्षेत्र पर मंडराते या चक्कर लगाते हैं।

इन सभी हमलों में भारतीय संपत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, जो हमारी निगरानी, योजना और वितरण प्रणालियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। आधुनिक स्वदेशी तकनीक के उपयोग ने लंबी दूरी के ड्रोन से लेकर निर्देशित हथियारों तक इन हमलों को अत्यधिक प्रभावी और राजनीतिक रूप से संतुलित बनाया।

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को आपूर्ति की गई चीनी हवाई सुरक्षा प्रणालियों को दरकिनार कर दिया और उन्हें जाम कर दिया। इससे मात्र 23 मिनट में मिशन पूरा कर भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित किया गया।

खतरों को बेअसर करने के साक्ष्य

'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारतीय प्रणालियों द्वारा शत्रु देश की प्रौद्योगिकियों को बेअसर करने के ठोस सबूत भी पेश किए:

- पीएल-15 मिसाइलों के टुकड़े (चीन निर्मित)
- तुर्की निर्मित यूएवी, जिन्हें 'यीहा' या 'यीहाव' नाम दिया गया
- लंबी दूरी के रॉकेट, क्वाडकॉप्टर और वाणिज्यिक ड्रोन

इन्हें बरामद कर उनकी पहचान की गई, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान द्वारा विदेशों से हासिल किए गए उन्नत हथियारों का इस्तेमाल करने के प्रयासों के बावजूद भारतीय स्वदेशी वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नेटवर्क बेहतर बने रहे।

प्रणालियों का प्रदर्शन: भारतीय सेना के हवाई सुरक्षा उपाय

12 मई को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, महानिदेशक सैन्य संचालन ने 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित प्रेस ब्रीफिंग में विरासत और आधुनिक प्रणालियों के मिश्रण के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रकाश डाला:

तैयारी और समन्वय

- चूंकि, आतंकवादियों पर सटीक हमले नियंत्रण रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना किए गए थे, इसलिए यह अनुमान लगाया गया था कि इन्हें लेकर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी।
- सेना और वायु सेना दोनों की जवाबी मानव रहित हवाई प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सामग्रियों और वायु रक्षा हथियारों का एक अनूठा मिश्रण।

अंतरराष्ट्रीय सीमा से भीतर की ओर कई रक्षात्मक परतें:

- जवाबी मानव रहित हवाई प्रणालियां
- कंधे पर रखकर दागे जाने वाले हथियार
- पुराने वायु रक्षात्मक हथियारों का इस्तेमाल

आधुनिक वायु रक्षा हथियार प्रणालियां

इस बहु-स्तरीय सुरक्षा ने 9-10 मई की रात को हमारे हवाई अड्डों और सामरिक प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तानी वायु सेना के हमलों को रोका। पिछले एक दशक में लगातार सरकारी निवेश से निर्मित ये प्रणालियां इस ऑपरेशन के दौरान मनोबल बढ़ाने वाली साबित हुईं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि दुश्मन के जवाबी हमलों के दौरान भारत में नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचा दोनों ही बड़े पैमाने पर अप्रभावित रहे।

इसरो का योगदान: इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने 11 मई को एक कार्यक्रम में उल्लेख किया कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10 उपग्रह लगातार चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र को अपने उपग्रहों के माध्यम से अपने 7,000 किलोमीटर के समुद्री तट क्षेत्रों की निगरानी करनी है। इसे पूरे उत्तरी भाग की लगातार निगरानी करनी है। उपग्रह और ड्रोन तकनीक के बिना देश यह हासिल नहीं कर सकता।

ड्रोन पावर का व्यवसाय: एक उभरता हुआ स्वदेशी उद्योग

ड्रोन फेडरेशन इंडिया (डीएफआई), एक प्रमुख उद्योग निकाय है जो 550 से अधिक ड्रोन कंपनियों और 5500 ड्रोन पायलटों का प्रतिनिधित्व करता है। डीएफआई का लक्ष्य 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाना है और यह दुनिया भर में भारतीय ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक के डिज़ाइन, विकास, निर्माण, अपनाने और निर्यात को

बढ़ावा देता है। डीएफआई व्यापार करने में आसानी को सक्षम बनाता है, ड्रोन तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देता है और भारत ड्रोन महोत्सव जैसे कई कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। ड्रोन स्पेस में शामिल कुछ कंपनियां हैं:

- अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज (बेंगलुरु): स्काईस्ट्राइकर बनाने के लिए इज़राइल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ साझेदारी की।
- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स रक्षा और सुरक्षा में एकीकृत समाधानों की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है और छह दशकों से अधिक समय से भारत के सशस्त्र बलों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में काम कर रहा है।
- पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में काम करती है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित (आईडीडीएम) क्षमताओं के लिए जानी जाती है।
- आईजी ड्रोन्स रक्षा और अन्य उद्योग अनुप्रयोगों में विशेषज्ञता वाले ड्रोन के निर्माण, शोध एवं विकास के लिए एक ड्रोन प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह उद्योग विशेषज्ञों द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण, मानचित्रण और निरीक्षण जैसी ड्रोन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने भारतीय सेना, भारत सरकार, कई राज्य सरकारों आदि के साथ भागीदारी की है।

भारतीय ड्रोन बाजार 2030 तक $11 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो वैश्विक ड्रोन बाजार का 12.2 प्रतिशत है।

भारतीय ड्रोन बाजार 2030 तक $11 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो वैश्विक ड्रोन बाजार का 12.2 प्रतिशत है

आधुनिक युद्ध के केंद्र में ड्रोन

भारत के सैन्य सिद्धांत में ड्रोन युद्ध को शामिल करने की सफलता का श्रेय घरेलू शोध एवं विकास और नीति सुधार को जाता है। 2021 से आयातित ड्रोन पर प्रतिबंध और पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजना की शुरुआत ने तेजी से नवाचार को बढ़ावा दिया है। नागर विमानन मंत्रालय की ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन की योजना को 30 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24) में कुल 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया था। भविष्य एआई-संचालित निर्णय लेने वाले स्वायत्त ड्रोन में निहित है और भारत पहले से ही इसकी नींव रख रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात ने लगभग 24,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर लिया। इसका उद्देश्य 2029 तक इस आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र और दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश बनाना है।

मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र के विकास को गति दे रहा है

भारत 'मेक इन इंडिया' पहल और आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत प्रयास से प्रेरित होकर एक प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 से 34 गुना वृद्धि है।

रणनीतिक सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और ठोस अनुसंधान एवं विकास के कारण धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस), मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) अर्जुन, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच), लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एलयूएच), आकाश मिसाइल सिस्टम, वेपन लोकेटिंग रडार, 3डी टैक्टिकल कंट्रोल रडार और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एसडीआर) जैसे उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ-साथ विध्वंसक, स्वदेशी विमानवाहक पोत, पनडुब्बी, फ्रिगेट, कोरवेट, तेज गश्ती पोत, तेज गति से हमला करने वाले जहाज और अपतटीय गश्ती पोत जैसी नौसेना सामग्रियों का विकास हुआ है।

सरकार ने रिकॉर्ड खरीद अनुबंधों, आईडीईएक्स के तहत नवाचारों, सृजन जैसे अभियानों और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों के साथ इस वृद्धि को अपना समर्थन किया है। एलसीएच (लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर) प्रचंड हेलीकॉप्टर और एटीएजीएस (एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के लिए स्वीकृति) जैसे प्रमुख अधिग्रहण स्वदेशी क्षमता की ओर बदलाव को दर्शाते हैं। भारत 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये के निर्यात के लक्ष्य के साथ भारत खुद को एक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी रक्षा विनिर्माण शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित कर रहा है।

निष्कर्ष

'ऑपरेशन सिंदूर' केवल सामरिक सफलता की कहानी नहीं है। यह भारत की रक्षा स्वदेशीकरण नीतियों की पुष्टि है। वायु रक्षा प्रणालियों से लेकर ड्रोन तक, काउंटर-यूएएस क्षमताओं से लेकर नेट-केंद्रित युद्ध प्लेटफार्मों तक, स्वदेशी तकनीक ने तब काम किया है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। निजी क्षेत्र के नवाचार, सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन और सैन्य दृष्टि के संयोजन ने भारत को न केवल अपने लोगों और क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम बनाया है, बल्कि 21वीं सदी में एक हाई-टेक सैन्य शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को भी सक्षम बनाया है। भविष्य के संघर्षों में युद्ध के मैदान को तेजी से तकनीक द्वारा आकार दिया जाएगा, जैसाकि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने पूरी तरह साबित कर दिया है। भारत तैयार है, अपने स्वयं के नवाचारों से लैस है, एक दृढ़ राष्ट्र द्वारा समर्थित है और अपने नागरिकों की निष्कपटता से संचालित है। ■

पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार को मिली स्वीकृति

पिछले 10 वर्ष में 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख होकर 100 प्रतिशत बढ़ गई है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात मई को आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू- कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित पांच नए आईआईटी की शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता (चरण-बी निर्माण) के विस्तार को स्वीकृति दी।

- इसके लिए 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि में कुल लागत 11,828.79 करोड़ रुपये है।
- मंत्रिमंडल ने इन आईआईटी में 130 संकाय पदों (प्रोफेसर स्तर यानी लेवल 14 और उससे ऊपर) के सृजन को भी स्वीकृति दी है।
- उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पांच नए अत्याधुनिक अनुसंधान पार्क भी बनाए जा रहे हैं।

इन आईआईटी में विद्यार्थियों की संख्या अगले चार वर्षों में 6500 से अधिक बढ़ जाएगी, जिसमें स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी कार्यक्रम में प्रथम वर्ष में 1364 विद्यार्थी, द्वितीय वर्ष में 1738 विद्यार्थी, तृतीय वर्ष में 1767 विद्यार्थी और चतुर्थ वर्ष में 1707 विद्यार्थी बढ़ेंगे।

लाभार्थी

निर्माण पूरा होने पर ये पांच आईआईटी 7,111 की वर्तमान विद्यार्थी संख्या की तुलना में 13,687 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे, यानी 6,576 विद्यार्थियों की वृद्धि होगी। सीटों की कुल संख्या में इस वृद्धि के साथ अब 6,500 से अधिक अतिरिक्त विद्यार्थी देश के सबसे प्रतिष्ठित और मांग वाले शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

यह कुशल कार्यबल का निर्माण करके, नवाचार को बढ़ावा देकर और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देगा। यह सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाता है, शैक्षिक असमानता को कम करता है और भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्ष में 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख होकर 100 प्रतिशत बढ़ गई है। वर्ष 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आई.एल.टी. में 6,500 और अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मई को भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी। देश में पहले से ही पांच सेमीकंडक्टर इकाइयां निर्माण के उन्नत चरणों में हैं। इस छठी इकाई के साथ भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने की दिशा में और प्रगति कर रहा है।

आज स्वीकृत इकाई एचसीएल और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम है। हार्डवेयर विकसित करने और निर्माण करने का एचसीएल का लंबा अनुभव रहा है। फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में एक वैश्विक प्रमुख कंपनी है। दोनों मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या वाईईआईडीए में जेवर हवाई अड्डे के पास एक संयंत्र स्थापित करेंगे।

यह संयंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और डिस्प्ले संबंधी अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा। इस संयंत्र को 20,000 वेफर्स प्रति माह के अनुसार से डिजाइन किया गया है और इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह है।

सेमीकंडक्टर उद्योग अब पूरे देश में विस्तारित हो रहा है। देश भर के कई राज्यों में विश्व स्तरीय डिजाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य सरकारें डिजाइन फर्मों को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही हैं।

270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप में छात्र और उद्यमी नए उत्पादों के विकास के लिए विश्व स्तरीय नवीनतम डिजाइन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विकसित 20 उत्पादों को एससीएल मोहाली द्वारा टेप आउट (डिजाइन चरण-आवश्यक सत्यापन और मान्यता चरण को पूरा करने की प्रक्रिया) किया गया है।

आज स्वीकृत नई सेमीकंडक्टर इकाई पर अनुमानित निवेश 3,700 करोड़ रुपये है।

भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी सुविधाएं स्थापित की हैं। एप्लाइड मैटेरियल्स और लैम रिसर्च दो सबसे बड़े उपकरण निर्माता हैं और इन दोनों की अब भारत में उपस्थिति है। मर्क, लिंडे, एयर लिक्विड, आईनॉक्स और कई अन्य गैस और रासायनिक आपूर्तिकर्ता हमारे सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भारत में लैपटॉप, मोबाइल फोन, सर्वर, चिकित्सा उपकरण, बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के तेजी से विकास के साथ सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ रही है, यह नई इकाई प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाएगी। ■

मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख जन्मों से उल्लेखनीय रूप से घटकर 93 हुई

शिशु मृत्यु दर 2014 में 39 प्रति 1000 जन्मों से घटकर 2021 में 27 प्रति 1000 जन्मों पर आ गई

भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा 07 मई, 2025 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रमुख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) पर आधारित भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2019-21 के अनुसार देश के मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में उल्लेखनीय कमी आई है। यह 2014-16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 से 37 अंक घटकर 2019-21 में 93 हो गई है।

इसी प्रकार नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2021 के अनुसार शिशु मृत्यु दर संकेतकों में गिरावट का रुझान जारी रहा। देश की शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 2014 में प्रति 1000 जन्मों पर 39 से घटकर 2021 में प्रति 1000 जन्मों पर 27 हो गई है। नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) 2014 में प्रति 1000 जन्मों पर 26 से घटकर 2021 में प्रति 1000 जन्मों पर 19 हो गई है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) 2014 में प्रति 1000 जन्मों पर 45 से घटकर 2021 में प्रति 1000 जन्मों पर 31 हो गई है। जन्म के समय लिंग अनुपात 2014 में 899 से सुधरकर 2021 में 913 हो गया है। कुल प्रजनन दर 2021 में 2.0 पर स्थिर है, जो 2014 में 2.3 से उल्लेखनीय सुधार है। ■

अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025 के दौरान कोयला आयात में 9.2 प्रतिशत की कमी

कोयला आयात में कमी के परिणामस्वरूप लगभग 6.93 बिलियन डॉलर (53,137.82 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा की बचत हुई

केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा 13 मई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025 के दौरान देश में कोयले का आयात 9.2 प्रतिशत घटकर 220.3 मिलियन टन (एमटी) रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 242.6 एमटी था। इस कमी के परिणामस्वरूप लगभग 6.93 बिलियन डॉलर (53,137.82 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। उल्लेखनीय रूप से बिजली क्षेत्र को छोड़कर गैर-विनियमित क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण गिरावट आई, जिसमें आयात में साल-दर-साल 15.3 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, कोयला आधारित बिजली उत्पादन में अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025 तक पिछले वर्ष की तुलना में 2.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन थर्मल पावर प्लांट द्वारा मिश्रण के लिए आयात में 38.8 प्रतिशत की तीव्र कमी आई।

भारत सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन और मिशन कोकिंग कोल सहित कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 5.45 प्रतिशत की उत्साहजनक वृद्धि हुई है। ■

वित्त वर्ष 2024-25 में खनन में रिकॉर्ड उत्पादन

केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा पांच मई को जारी एक बयान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन स्तर पर पहुंचने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुछ प्रमुख खनिजों के उत्पादन में मजबूत वृद्धि देखी गई। मूल्य के हिसाब से कुल एमसीडीआर खनिज उत्पादन में लौह अयस्क का योगदान 70 प्रतिशत है। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में 289 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) लौह अयस्क के उत्पादन ने 4.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में हासिल किए गए 277 एमएमटी के उत्पादन रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

इसी तरह, मैंगनीज अयस्क का उत्पादन भी वित्त वर्ष 2023-24 में हासिल किए गए 3.4 एमएमटी के उत्पादन रिकॉर्ड को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 11.8 प्रतिशत बढ़कर 3.8 एमएमटी हो गया है। बॉक्साइट का उत्पादन भी वित्त वर्ष 2023-24 में 24 एमएमटी से 2.9 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 24.7 एमएमटी हो गया है। इसी अवधि के दौरान सीसा सांद्रण उत्पादन 3.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ 381 हजार टन (टीएचटी) से बढ़कर 393 टीएचटी हो गया।

गैर लौह धातु क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024-25 में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन ने वित्त वर्ष 2023-24 के उत्पादन रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन 41.6 लाख टन (एलटी) था, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यह बढ़कर 42 एलटी हो गया। रिफाइंड कॉपर उत्पादन में 12.6 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 5.09 एलटी था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 5.73 एलटी हो गया।

उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक, रिफाइंड कॉपर में शीर्ष 10 उत्पादकों में से एक और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। ■

'मोदी सरकार 31 मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 मई को कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में सीपीआई-माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बासवराजू सहित 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है। गृह मंत्री ने इस बड़ी सफलता के लिए बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना की।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हई है। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया, जिनमें नंबाला केशव राव उर्फ बासवराजू भी शामिल है, जो सीपीआई-माओवादी का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ था। यह पहली बार है जब भारत की नक्सलवाद के खिलाफ तीन दशकों की लड़ाई में महासचिव स्तर के नेता को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है।

गृह मंत्री ने कहा कि इस बड़ी सफलता के लिए वे हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करते हैं। श्री शाह ने कहा कि यह भी खुशी की बात है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मोदी सरकार 31 मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने माओवाद की त्रासदी को दूर करने को लेकर बलों के प्रयासों की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 मई को माओवाद की त्रासदी को दूर करने और लोगों के लिए शांति तथा प्रगति का जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए बलों के प्रयासों की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 'एक्स' पर एक पोस्ट के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा, "इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए हमें अपने बलों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद की त्रासदी को दूर करने और लोगों के लिए शांति तथा प्रगति का जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

मुख्य बातें

- नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया
- मारे गए 27 खूंखार माओवादियों में नंबाला केशव राव उर्फ बासवराजू भी शामिल है, जो सीपीआई-माओवादी का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ था
- यह पहली बार है जब भारत की नक्सलवाद के खिलाफ तीन दशकों की लड़ाई में महासचिव स्तर के नेता को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया
- गृह मंत्री ने इस बड़ी सफलता के लिए बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना की
- ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया
- मोदी सरकार 31 मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध ■

जीइएम पोर्टल ने भारत की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को कैसे बदला

पीयूष गोयल

सार्वजनिक खरीद के लिए पारदर्शी, समावेशी एवं कुशल मंच प्रदान करने के अग्रणी उपाय के रूप में गवर्नमेंट इ-मार्केटप्लेस (जीइएम) पूरी दुनिया में तेजी से उभरा है। यह प्लेटफॉर्म 1.6 लाख से अधिक सरकारी खरीदारों को 23 लाख विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं से जोड़ रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण का एक प्रमुख वाहक बन गया है।

इस डिजिटल पहल के माध्यम से पिछले नौ वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया और स्टार्टअप, एमएसएमइ, महिलाओं एवं छोटे शहरों के व्यवसायों को अवसर प्रदान कर सरकारी खरीद के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाया गया है। उपयोगकर्ताओं के अनुकूल माने जाने वाले इस प्लेटफॉर्म ने आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाइज एंड डिस्पोजल्स) की जगह ले ली है।

वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद से ही जीइएम पोर्टल पर 13.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर का लेन-देन किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक खरीद बढ़कर रिकॉर्ड 5.43 लाख करोड़ रुपये की हो गयी। जीइएम का लक्ष्य वर्तमान वित्त वर्ष में अपने वार्षिक कारोबार को बढ़ाकर सात लाख करोड़ रुपये करना है। इसने ईमानदारी से व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठानों को व्यापक अवसर प्रदान किये हैं, नौकरियां सृजित की हैं और भारत के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है। अपनी प्रगति के कारण निकट भविष्य में यह विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक खरीद पोर्टल बन जाएगा तथा दक्षिण कोरिया के कोनेप्स जैसी सुप्रतिष्ठित संस्थाओं को भी पीछे छोड़ देगा।

वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद से ही जीइएम पोर्टल पर 13.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर का लेन-देन किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक खरीद बढ़कर रिकॉर्ड 5.43 लाख करोड़ रुपये की हो गयी। जीइएम का लक्ष्य वर्तमान वित्त वर्ष में अपने वार्षिक कारोबार को बढ़ाकर सात लाख करोड़ रुपये करना है

जीइएम प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' मिशन के अनुरूप न्यायसंगत विकास के एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में कार्य करता है। यह स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों एवं महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बिना किसी बिचौलियों के अपने उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने का एक आसान रास्ता प्रदान करता है। यह पोर्टल सभी बाधाओं को दूर कर छोटे घरेलू व्यवसायों को इ-टेंडर में भाग लेने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अधिकार देता है। छोटे व्यवसायों के विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से विभिन्न रणनीतिक पहलों को इसमें शामिल किया गया है।

समावेशिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर जीइएम ने छोटे व्यवसायों के विकास को समर्थन दिया है। इनमें सरकारी खरीदारों को एमएसएमई और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों की पहचान करने और उनका चयन करने में मदद करने वाली प्रणालियां शामिल हैं।

जीइएम पर 'स्टार्टअप रनवे' और 'वुमनिया' जैसे समर्पित स्टोरफ्रंट ने इन व्यवसायों की दृश्यता के साथ-साथ सार्वजनिक खरीद में इनकी हिस्सेदारी को भी प्रभावी ढंग से बढ़ाया है। इससे सरकार को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमइ) से 25 प्रतिशत खरीद और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों से तीन प्रतिशत खरीद के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली है। जीइएम पर किये गये कुल कारोबार का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमइ) के पास है और वही महिला उद्यमों से लगभग चार प्रतिशत खरीदारी की गयी है।

अप्रैल 2025 तक 30,000 से अधिक स्टार्टअप ने जीइएम के जरिये 38,500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। इसके अतिरिक्त, 1.81 लाख महिला उद्यमियों ने जीइएम पोर्टल पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किये हैं।

ऐसे ही कुछ खास ऑर्डरों पर 33 प्रतिशत से लेकर 96 प्रतिशत तक की बचत हुई है। यह बदलाव न केवल हमारे नागरिकों के हित में है, बल्कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं इज ऑफ लिविंग जैसे लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार हैं।

विश्व बैंक के एक स्वतंत्र मूल्यांकन

के अनुसार जीइएम पर खरीदार औसत कीमत पर लगभग 9.75 प्रतिशत की बचत करते हैं। इससे करदाताओं के पैसे का उपयोग करके की जाने वाली सार्वजनिक खरीद में अनुमानित रूप से 1,15,000 करोड़ रुपये की भारी बचत हुई है। जीइएम खरीद से सरकारी कंपनी एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपये के अनुबंध में रिवर्स नीलामी का उपयोग करके 2,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली। जीइएम ने रक्षा उपकरण, टीके, ड्रोन और बीमा जैसी सेवाओं की पारदर्शी और लागत प्रभावी खरीद में भी मदद की है।

छोटे उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए जीइएम ने हाल ही में अपने लेन-देन शुल्क में उल्लेखनीय कमी की है। 10 लाख रुपये से अधिक के ऑर्डर पर 0.30 प्रतिशत का कम लेन-देन शुल्क लगेगा, जबकि 10 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पर 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा होगी - जो कि पहले 72.50 लाख रुपये थी।

जीईएम पोर्टल समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने एवं उनका उत्थान करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा अतिरिक्त प्रयास करेगा

यह प्लेटफॉर्म विभिन्न तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर व्यापार करने के नये एवं आसान तरीके प्रदान कर, लगातार विकसित हो रहा है। जीइएम ने 'जीइएम एआइ' नामक एक एआइ संचालित चैटबॉट का समावेश किया है। यह स्मार्ट चैटबॉट आठ स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है और जीइएम पोर्टल पर व्यापार करने को और आसान करने के लिए वॉयस कमांड कार्यक्षमता सहित नवीनतम तकनीकों से लैस है। जीइएम सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमइ) विक्रेताओं के लिए वित्तपोषण संबंधी उत्पाद भी प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने जीइएम सहाय 2.0 पेश किया है, जो 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करता है। जीइएम पोर्टल भारत के आर्थिक विकास और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रगति संबंधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में सक्रिय है। यह समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने एवं उनका उत्थान करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा अतिरिक्त प्रयास करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि करदाताओं के पैसे का कुशलतापूर्वक उपयोग प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की खरीद के लिए किया जाए। ■

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं)

ऑपरेशन सिंदूर

साहस, शक्ति और नए भारत की ललकार

तरुण चुग

आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सैन्य नीति को एक नई दिशा दी है। यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि नए भारत की चेतावनी हैः अगर हमें छेड़ा जाएगा, तो छोड़ा नहीं जाएगा। एक भारतीय नागरिक और भाजपा के एक कार्यकर्ता के रुप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और हमारी सेनाओं के पराक्रम पर गर्व करता हूं।

यह सब उस क्रूर आतंकी घटना से शुरु हुआ जिसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में धार्मिक यात्रियों और पर्यटकों पर हमला हुआ। केवल उनके धर्म के कारण निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मार डाला गया। परिवारों के सामने उनके अपनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वीभत्स नरसंहार में 28 निर्दोष नागरिकों की जान गई। पूरे देश में रोष और शोक की लहर थी। पहलगाम की त्रासदी के बाद जो आवाजें उठीं, वे कह रही थीं— अब और नहीं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस वेदना को संकल्प में बदला। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस नरसंहार के दोषियों को भारत की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। न अब सिर्फ बयानबाजी होगी, न सीमित प्रतिक्रियाएं। अब भारत न्याय दिलाने के लिए जो भी जरूरी हो, करेगा।

निर्णय उच्चतम स्तर पर स्पष्टता के साथ लिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व हमेशा निर्णायक, गतिशील और साहसी रहा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में उन्होंने अपने ही मानकों को पार कर दिया। उन्होंने हमारी सेनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दी— किसी भी स्थान पर आतंक को कुचलने की छूट। अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, अब कोई विलंब नहीं था। वर्षों बाद भारत की प्रतिक्रिया केवल सीमा पर जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सीधा दुश्मन की मांद में घुसने का ऐलान था। मैं उस समय लिए गए निर्णयों का साक्षी रहा-संदेश साफ थाः पहलगाम में गिरी हर बेकसूर भारतीय की बूंद-बूंद का हिसाब लिया जाएगा। अब 'संयम' वाला पुराना पत्रा फाड़ दिया गया था। नया भारत अब हर आतंकी हमले को युद्ध मानकर उत्तर देगा।

और तब शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर- एक ऐसा नाम जो उस पवित्र सिंदूर का प्रतीक है जिसे आतंकियों ने मिटाने की कोशिश की थी। 7 मई की भोर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओजेके के अंदर घुसकर साहसिक हमला किया। बहावलपुर, मुरीदके, मुज़फ्फराबाद जैसे आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने सटीक एयरस्ट्राइक की। ये वो गढ़ थे जहां वर्षों से वैश्विक जिहाद की फैक्ट्रियां चल रही थीं। उस रात हमारी मिसाइलों ने इन अड्डों को मलबे में बदल दिया।

पाकिस्तान बौखलाहट में आगबबूला हो गया। आतंक को खत्म करने की बजाय, उसने भारतीय नागरिक क्षेत्रों पर रॉकेट और तोप से हमला किया। लेकिन भारत पूरी तरह तैयार था। हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने हर हमले को निष्क्रिय कर दिया। एक भी भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया नाकाम रही।

खबरें आने लगीं— सिर्फ पहले हमले में ही 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों का

सफाया कर दिया गया। इनमें कई शीर्ष कमांडर भी थे जो पाकिस्तान की शरण में ऐश कर रहे थे और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे थे। उन्हें लगा था कि सीमा पार होने से वे सुरक्षित हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी यह गलतफहमी हमेशा के लिए तोड़ दी। भारत ने यह साबित कर दिया कि उसके न्याय का हाथ बहुत लंबा है। जिन लोगों ने हमारे निर्दोषों की हत्या की, उन्हें एक ही वार में खत्म कर दिया गया। यह न्याय था— ठंडा, सटीक और निष्पक्ष।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया वही रही- हैरानी, इनकार और पागलपन। पहले कुछ घंटों तक उनके जनरल सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि भारत इतनी गहराई तक हमला कर सकता है। लेकिन फिर वही पुरानी कायरता सामने आई। आतंक को खत्म करने की बजाय, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसका निशाना हमारे नागरिक और सीमावर्ती गांव थे। अंतर देखिए: भारत ने आतंकियों को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने नागरिकों को।

इसके बाद आया दूसरा चरण। 10 मई को भारत ने फिर हमला किया— इस बार पाकिस्तान की सैन्य संरचना को लक्ष्य बनाया गया। सरगोधा, स्कर्दू, जैकबाबाद और भोलारी जैसे एयरबेस पर हमले किए गए। इस्लामाबाद के पास स्थित नूर स्थान एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ टूट गई। उनके F-16 लड़ाकू विमान ज़मीन से उठ ही नहीं सके। उनके जनरल स्तब्ध रह गए।

जब सैन्य मोर्चे पर भी वे असफल हो गए, तो पाकिस्तान घबरा गया। लेकिन भारत का अभियान अभी पूरा नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण और भी विनाशकारी था। इसने पाकिस्तान की रक्षा शक्ति और उसके आत्मबल को पूरी तरह तोड़ डाला। 10 मई की भोर में, जब पाकिस्तान अपने ज़ख्मों को सहला रहा था, हमारी वायुसेना ने एक के बाद एक हमले कर पाकिस्तान के सैन्य ठांचे को तहस-नहस कर दिया।

इस बार लक्ष्य थे— सरगोधा, स्कर्दू, जैकबाबाद, सुक्कुर और कराची के पास भोलारी। हर जगह धमाके हुए। हमारे लड़ाकू विमान भारतीय वायुक्षेत्र से मिसाइल दाग रहे थे और लंबी दूरी की तोपें सीमा पार कर वार कर रही थीं। 20-25 मिनट में पाकिस्तान की कई एयरबेस ठप हो गईं।

एक विशेष हमले का ज़िक्र आवश्यक है— रावलपिंडी के चकलाला स्थित नूर खान एयरबेस पर हुआ प्रहार। यह पाकिस्तान की सैन्य कमान और परमाणु नियंत्रण का केंद्र है। इसे निशाना बनाकर भारत ने स्पष्ट संदेश दिया— यदि आतंक को समर्थन दोगे, तो तुम्हारी सबसे सुरक्षित एयर बेस भी बच नहीं पाएगी। उस हमले ने पाक सेना के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। वर्षों तक पाकिस्तान ने 'परमाणु धमकी' की ढाल ली हुई थी। 10 मई को वह भ्रम चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान का कोई कोना भारत की पहुंच से बाहर नहीं रहा।

यहीं से पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की गुहार लगाई। जो देश पहले धमकी देता था, अब शांति की भीख मांग रहा था। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट किया— भारत ने अपने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, पर यह अंत नहीं, सिर्फ विराम है। भविष्य में कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। हमारी नीति बदल चुकी है।

ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, एक रणनीतिक सिद्धांत है। अब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हम कार्रवाई करते हैं। अब हम सहन नहीं करते, हम खत्म करते हैं। यही है नया भारत। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय साहस, सटीकता और व्यावसायिकता दिखाई। राफेल उड़ानों ने दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त किया। मिसाइल यूनिट्स ने शल्य जैसी मार की। नौसेना ने समुद्र पर पकड़ बनाई। यह सामूहिक विजय थी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जवानों को सलामी दी। उन्होंने गरजकर कहा— "भारत माता की जय" जब हमारे जवान बोलते हैं, तो दुश्मन कांपते हैं। उन्होंने कहा— हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नहीं, पाकिस्तान के घमंड को भी चूर कर दिया है।

'टूलकिट गिरोह' वामपंथी-उदारवादी गठजोड़ ने हमेशा की तरह इस विजय को कमतर आंकने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाए, सबूत मांगे, और दुश्मन की भाषा बोले। लेकिन देश की जनता ने उनकी झूठी कहानियों को नकार दिया। जनता मोदी जी और हमारी सेना के साथ खड़ी रही।

ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, आत्मविश्वास से भरे भारत की घोषणा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्पष्ट कर दिया है— अब हम पहले प्रहार करेंगे, कड़ा प्रहार करेंगे, और वहीं प्रहार करेंगे जहां सबसे ज़्यादा दर्द होगा।

हमने 'परमाणु ब्लैकमेल' की नौटंकी को उजागर कर दिया है। हमने नई रेड लाइन खींच दी है— अब आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।

हमारे सैनिकों को कोटि-कोटि नमन। प्रधानमंत्री श्री मोदी को राष्ट्र का गौरव बनाने के लिए धन्यवाद। और हमारे दुश्मनों को संदेश स्पष्ट है— अब कभी नहीं। ■

भारत माता की जय।

जय हिंद।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

एक नए बस्तर का निर्माण

विष्णुदेव साय

करीब चार दशकों तक बस्तर वामपंथी उग्रवाद के साये में रहा। आज यह बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। आदिवासी बहुल इलाकों के लोगों के लिए लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं रणनीतिक सुरक्षा अभियानों के कारण अब भय का स्थान एक उम्मीद की किरण ने ले लिया है।

छत्तीसगढ़ की आदिवासी विरासत से प्रेरित हमारी सरकार एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध क्षेत्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, हम अपने लोगों की समृद्ध संस्कृति से प्रेरणा लेते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है— अगले साल मार्च तक दशकों से चले आ रहे उग्रवाद को खत्म करना और बस्तर के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाना। हमारी सरकार 2023 में सत्ता संभालने के बाद से ही इस क्षेत्र के लोगों के साथ सीधे जुड़ाव को प्राथमिकता दे रही है। मैंने अब तक 77 बार बस्तर का दौरा किया है और इस दौरान मुख्य रूप से स्थानीय जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाओं को आकार देने का काम किया गया है।

ये दौरे प्रशासनिक कर्तव्यों से कहीं बढ़कर हैं। ये ग्रामीणों के साथ चलने, उनकी आकांक्षाओं को सुनने और यह सुनिश्चित करने के लिए दिल से किए गए प्रयास हैं कि प्रगति की बयार उनके दरवाजे तक पहुंचे। बस्तर की बहुसंख्यक आदिवासी आबादी का सरकार पर भरोसा तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि उनमें से ही एक व्यक्ति अब हमारा नेतृत्व कर रहा है और प्रशासनिक पहलों में ठोस नतीजे आ रहे है। इस जुड़ाव ने समुदायों को आश्वस्त किया है कि मेरी सरकार कार्रवाई करने और संघर्ष के घावों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है।

कभी बारूद की तीखी गंध से महकती बस्तर की हवा में आज महुआ के फूलों की खुशबू है, जो आदिवासी जीवन का एक प्रतीक है। कभी सुनसान रहने वाले बाजार आज व्यापार के जीवंत केंद्र बन गए हैं। उग्रवादियों द्वारा बंद किए गए स्कूल अब छात्रों का स्वागत कर रहे हैं। सुकमा में 50 से अधिक प्राथमिक विद्यालय फिर से खोले गए हैं और सात नए स्कूल स्थापित किए गए हैं। कभी उग्रवादियों के कब्जे में रहने वाली सड़कें अब जीवन से गुलजार हैं।

> **कभी बारूद की तीखी गंध से महकती बस्तर की हवा में आज महुआ के फूलों की खुशबू है, जो आदिवासी जीवन का एक प्रतीक है। कभी सुनसान रहने वाले बाजार आज व्यापार के जीवंत केंद्र बन गए हैं। उग्रवादियों द्वारा बंद किए गए स्कूल अब छात्रों का स्वागत कर रहे हैं। सुकमा में 50 से अधिक प्राथमिक विद्यालय फिर से खोले गए हैं और सात नए स्कूल स्थापित किए गए हैं। कभी उग्रवादियों के कब्जे में रहने वाली सड़कें अब जीवन से गुलजार हैं**

बस्तर में सामान्य स्थिति और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा की स्थापना की गई है। यह एक सुदूर और ऐतिहासिक रूप से अस्थिर क्षेत्र है, जिसने दशकों तक उग्रवाद का सामना किया है। इस पहल से 12 गांवों के निवासियों को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी।

बस्तर ओलंपिक के साथ-साथ बस्तर पंडुम जैसे पारंपरिक आदिवासी त्योहारों को धूमधाम से मनाना इस क्षेत्र की विरासत को संजोते हुए विकास को अपनाने की इच्छा को दर्शाता है। यह बदलाव केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का नतीजा है।

पिछले 17 महीनों में 1,355 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और पुनर्वास तथा बेहतर जीवन का विकल्प चुना है। लगभग 1,429 अन्य को गिरफ्तार किया गया है तथा 420 से अधिक उग्रवादियों को मार गिराया गया है। उग्रवादियों का नेटवर्क काफी हद तक कमजोर हो गया है। राज्य पुलिस ने पाया है कि हिंसक घटनाओं में 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

छत्तीसगढ़ की नई नीति - जो 120 दिनों के भीतर पुनर्वास की गारंटी देती है - हथियार छोड़ने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में मदद कर रही है। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के सुदूर गांवों तक आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी को प्राथमिकता दी है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा और विकास कार्यों के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए जा रहे हैं।

फरवरी, 2024 में 20 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई नियाद नेला नार योजना, जिसे स्थानीय बोली में 'आपका अच्छा गांव' कहा जाता है, 130 माओवाद प्रभावित गांवों में आदिवासी परिवारों तक सीधे सरकारी योजनाएं पहुंचाती हैं। यहां मौजूद 61 सुरक्षा शिविरों को अब सुविधा केंद्रों में तब्दील किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे पहलों को लागू करने में निर्णायक

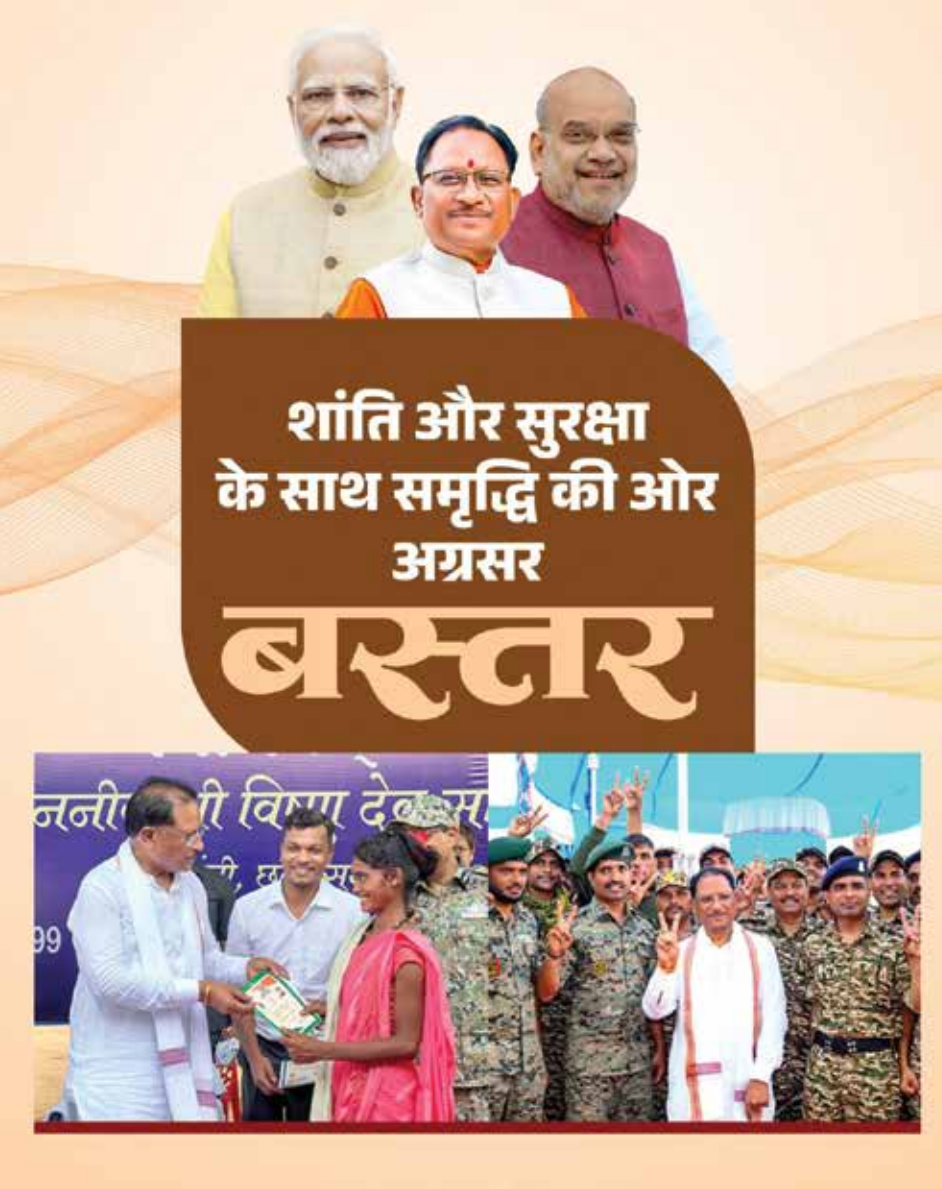

हमारी सरकार एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां बस्तर अवसरों के केंद्र के रूप में विकसित हो। 300 किलोमीटर से अधिक नई सड़कें निर्माणाधीन हैं, जो दूरदराज के गांवों को बाजारों और सेवाओं से जोड़ती हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र बस्तर के युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं

भूमिका निभा रहे है। जगरगुंडा और चार अन्य स्थानों पर 25 वर्षों से बंद वन विभाग के कार्यालय फिर से खुल गए हैं, जिससे बस्तर के मुख्य वन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था बहाल हो गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं, जिससे आदिवासी परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवनयापन का अधिकार मिला है। जल जीवन मिशन ने लगभग 1.2 लाख परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया है, जिससे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

वन आधारित आजीविका के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने तेंदू पत्ता (इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है) की कीमत 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। ये प्रयास बस्तर के विविध आदिवासी समुदायों, जिनमें गोंड, मारिया और मुरिया शामिल हैं, की ज़रूरतों के हिसाब से किए गए हैं। जन आशीर्वाद यात्राओं और जनसंपर्क अभियानों जैसी पहलों के ज़रिए हमारी सरकार ने लोगों की शिकायतों को सुना है। कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर सहित पूरे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण के जरिए काफी धन आवंटित किया गया है। सुकमा जिले को अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं।

हमारी सरकार एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां बस्तर अवसरों के केंद्र के रूप में विकसित हो। 300 किलोमीटर से अधिक नई सड़कें निर्माणाधीन हैं, जो दूरदराज के गांवों को बाजारों और सेवाओं से जोड़ती हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र बस्तर के युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। इकोटूरिज्म को बढ़ावा देकर और क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करके हमारी सरकार का लक्ष्य स्थायी आजीविका का निर्माण करना है, साथ ही दुनिया को बस्तर की सुंदरता देखने के लिए आमंत्रित करना है।

हिंसा को कम करना, समुदायों को सशक्त बनाना और बुनियादी ढांचे का निर्माण नये बस्तर के निर्माण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। वह दिन दूर नहीं जब वामपंथी उग्रवाद का दाग इस क्षेत्र से मिट जाएगा और इसके आदिवासी समुदाय विकास का जश्न मनाएंगे और एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध भविष्य को अपनाएंगे। ■

(लेखक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं)

जाति की गणना ही समावेशी हिंदुत्व है

गुरु प्रकाश

एनडीए सरकार ने 30 अप्रैल को आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति के आंकड़े एकत्र करने के अपने निर्णय की घोषणा की। इस घोषणा ने राजनीतिक हलकों एवं विश्लेषकों को चौंका दिया है। ऐसे देश में जहां जाति दैनिक जीवन और राजनीतिक गणित दोनों में गहराई से व्याप्त है, यह कदम न केवल नीतिगत बदलाव का प्रतीक है, बल्कि आधुनिक भारतीय शासन व्यवस्था में एक निर्णायक क्षण को भी दर्शाता है।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला समयानुकूल, साहसिक और दूरदर्शी है। इस फैसले को सभी दलों का समर्थन मिला है, खास तौर पर मेरे गृह राज्य बिहार में इसका खूब समर्थन किया गया। बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर ने एक बार कहा था कि भारत में अभी सामाजिक लोकतंत्र हासिल करना बाकी है। सरकार का यह कदम डॉ. अंबेडकर के विजन और मिशन को श्रद्धांजलि है। यह एक ऐसा कदम है जो सामाजिक न्याय एवं सामंजस्य को सुनिश्चित करेगा।

जनगणना में जाति के आंकड़ों को शामिल करना सिर्फ नौकरशाही का फैसला नहीं है। यह लंबे समय से लंबित बदलाव है। भारत ने पिछली बार विस्तृत जाति जनगणना 1931 में की थी। वह ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। तब से हम पुराने अनुमानों, राजनीतिक अटकलों और बेतरतीब सर्वेक्षणों पर निर्भर रहे हैं। यूपीए सरकार के तहत शुरू की गई 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) इस कमी को पूरा कर सकती थी, लेकिन यह विसंगतियों, कम रिपोर्ट किए गए आंकड़ों का शिकार हो गयी और इसे कभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया। यह एक खोया हुआ अवसर था, और शायद असहज सच्चाइयों का सामना करने में राजनीतिक हिचकिचाहट का प्रतिबिंब था।

इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह ऐसा कदम नहीं उठा पाए। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनीं, तो श्री मोदी ने अपने भाषणों में जोर देकर कहा कि समाज के वंचित वर्ग इस सरकार के केंद्र में हैं। जाति जनगणना की घोषणा ने इस बात की पुष्टि की है। यह याद रखना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी गुजरात में ओबीसी समुदाय से आते हैं और अथक परिश्रम के साथ वे मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री चुने गए।

> **लगभग एक सदी से जनगणना में जाति की गणना नहीं की गई है। इसका दोष सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय के प्रति उदासीन रवैये को जाता है। कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के खिलाफ रही है क्योंकि वह सामाजिक दरारों को भरने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है**

लगभग एक सदी से जनगणना में जाति की गणना नहीं की गई है। इसका दोष सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय के प्रति उदासीन रवैये को जाता है। कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के खिलाफ रही है क्योंकि वह सामाजिक दरारों को भरने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी केवल अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हितों में रुचि रखते हैं। सामाजिक न्याय के उनके आह्वान झूठ और पाखंड से भरे हुए हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के सामाजिक न्याय और जाति जनगणना में भी कई खामियां थीं।

मोदी सरकार के हस्तक्षेप से अब जाति जनगणना के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव के अंतिम नागरिक को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस मुद्दे पर राज्य-स्तरीय विभाजन से आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार अब मानव-केंद्रित विकास को बढ़ावा देने वाली और समाज को एक साथ लाने वाली जनगणना करने और इस प्रक्रिया मे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पुष्टि करेगा कि हम एक हैं। कांग्रेस को यह याद रखना चाहिए कि कैसे उसने डॉ. बी आर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम जैसे बड़े दलित नेताओं को कम महत्व दिया है और अब पार्टी के नेता दलित सशक्तीकरण के अपने झूठे प्रचार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

अगली जनगणना में जातिगत डेटा जोड़ना सिर्फ एक नौकरशाही कदम नहीं है। यह एक राजनीतिक और नैतिक मील का पत्थर है। यह विपक्ष के इस दावे को चुनौती देता है कि भाजपा जाति-आधारित असमानताओं के मामले में उचित रवैया नहीं अपनाती है।

उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनावों के नतीजे एक दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। इसमें भाजपा के समावेशी हिंदुत्व और विभिन्न जातियों तक पहुंच की रणनीति ने मतदाताओं को प्रभावित किया है, जिसने इस कथन को कमजोर किया है कि केवल जातिगत अंकगणित ही चुनाव जीतता है। विपक्ष का यह मानना कि जातिगत जनगणना से संतुलन अपने आप बदल जाएगा, गलत साबित हुआ।

मोदी सरकार का निचले तबके को सशक्त बनाने का संकल्प उसके पूरे कार्यकाल में

स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। चाहे वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना हो या भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाना हो या फिर निचले तबके के नेताओं को मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री बनाकर सरकारों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना हो। इन कदमों से देश को पता चलता है कि हम न केवल निचले तबके के लोगों की परवाह करते हैं, बल्कि उन्हें सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बिठाने के लिए भी दृढ़ संकल्पित है।

सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव — जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सहयोगी हैं — एक पोस्टर में नजर आए, जिसमें आधे फ्रेम पर उनका चेहरा था और आधे पर बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर का। समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को दलितों और उनके प्रतीकों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और उन्होंने उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेतृत्व किया है और रास्ता दिखाया है। आजादी के 78 साल बाद भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपना सही स्थान प्राप्त कर रहा है। जाति जनगणना को एक नीतिगत अनिवार्यता के रूप देखा जाना चाहिए है और इसी तरह दुनिया के समक्ष रखना चाहिए, ताकि यह बताया जा सके कि भारत विभिन्न सामाजिक विविधताओं के बावजूद एक स्थिर राष्ट्र है। हालांकि यह रातों-रात नहीं होगा, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार जनगणना की प्रक्रिया में वेब 3.0 तकनीक का पूरा लाभ उठाएगी, जिससे दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता का पता चलेगा। जाति गणना के साथ भारत के नीति निर्माता सार्वजनिक नीतियों को नया आकार देने में सक्षम होंगे जो नागरिकों की जिंदगी में वास्तविक सुधार लाएंगे। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

प्रधानमंत्री ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन (ग्लेक्स) 2025 को किया संबोधित

'भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन 'गगनयान' अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन (ग्लेक्स) 2025 को संबोधित किया। दुनिया भर से आए विशिष्ट प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए उन्होंने भारत की उल्लेखनीय अंतरिक्ष प्रगति पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष केवल एक गंतव्य नहीं है, बल्कि जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति की घोषणा है। उन्होंने कहा कि 1963 में एक छोटे रॉकेट को लॉन्च करने से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनने तक भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां इसी भावना को दर्शाती हैं।

श्री मोदी ने 2014 में अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने की भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि को याद किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज में मदद की, चंद्रयान-2 ने चंद्र सतह की हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें दीं और चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर हमारी समझ को गहराई दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने रिकॉर्ड समय में क्रायोजेनिक इंजन विकसित किए, एक ही मिशन में 100 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया और भारतीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग करके 34 देशों के लिए 400 से अधिक उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। इस वर्ष अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को डॉक करने की भारत की नवीनतम उपलब्धि का उल्लेख करते हुए इसे अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ा कदम बताया।

श्री मोदी ने कहा कि भारत नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार वैज्ञानिक अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन 'गगनयान' अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि आगामी हफ्तों में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसरो और नासा के एक संयुक्त मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा करेगा।

उन्होंने मछुआरों को सतर्क करने के लिए अपनाई गई चेतावनी की व्यवस्था, गतिशक्ति प्लेटफॉर्म, रेलवे सुरक्षा और मौसम की भविष्यवाणी में उपग्रहों के योगदान का हवाला देते हुए प्रत्येक भारतीय के कल्याण को सुनिश्चित करने में इन उपग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। श्री मोदी ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को स्टार्टअप, उद्यमियों और युवा प्रतिभाओं के लिए खोलकर नवाचार को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत में अब 250 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं जो उपग्रह प्रौद्योगिकी, प्रणोदन प्रणाली, इमेजिंग और अन्य अग्रणी क्षेत्रों में प्रगति में योगदान दे रहे हैं। ■

रिपोर्ट

एक-एक उड़ान से भारत को जोड़ना

"विमानन को कभी कुछ चुनिंदा लोगों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन उड़ान के आगमन के बाद अब यह बदल गया है। मेरा सपना है कि मैं हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति को हवाई जहाज़ में उड़ते हुए देखूं।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

625 उड़ान मार्ग चालू किए गए हैं जो पूरे भारत में 90 हवाई अड्डों (2 जल हवाई अड्डों और 15 हेलीपोर्ट सहित) को जोड़ते हैं। उड़ान के अंतर्गत 1.49 करोड़ से अधिक यात्री किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं

लंबे समय से आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाने वाला आकाश कभी भारत में कई लोगों के लिए एक अप्राप्य सपना था। इस अंतर को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान ('उड़े देश का आम नागरिक') का शुभारंभ किया। यह प्रधानमंत्री के इस विजन पर आधारित है कि हवाई चप्पल पहनने वाला एक आम आदमी भी हवाई यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। उड़ान का उद्देश्य सभी के लिए उड़ान को सुलभ और किफ़ायती बनाकर विमानन को बढ़ावा देना है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस प्रमुख योजना ने तब से भारत के क्षेत्रीय संपर्क परिदृश्य को बदल दिया है।

आम नागरिक के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना पहली उड़ान के साथ साकार हुआ। यह ऐतिहासिक उड़ान 27 अप्रैल, 2017 को शुरू हुई थी, जो शिमला की शांत पहाड़ियों को दिल्ली के हलचल भरे महानगर से जोड़ती है। 27 अप्रैल, 2025 को भारतीय विमानन क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत हुई, जिसने अनगिनत नागरिकों के लिए आसमान खोल दिया। इसे 8 साल पूरे हो जाएंगे।

उड़ान योजना की परिकल्पना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) 2016 के तहत की गई थी, जिसका लक्ष्य 10 साल का है ताकि टियर-2 और टियर-3 शहरों को बाजार संचालित लेकिन वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से जोड़ा जा सके। इस योजना ने एयरलाइनों को रियायतों और व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) के माध्यम से क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे किफायती किराया और बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुई।

उड़ान योजना के घटक

- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ): किफायती किराया सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइनों को वित्तीय सहायता।
- वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए हवाई किराये की सीमा निर्धारित की गई।
- केंद्र, राज्य, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और निजी हवाईअड्डा संचालकों के बीच सहयोगात्मक शासन।

हितधारक प्रोत्साहन

सरकार ने कम आकर्षक बाजारों में उड़ानें संचालित करने के लिए एयरलाइनों को आकर्षित करने हेतु कई उपाय किए हैं:

हवाई अड्डा संचालक: वे आरसीएस उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क माफ करते हैं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) इन उड़ानों पर टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) नहीं लगाता है। इसके अलावा, रियायती मार्ग संचालन और सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) लागू किया जाता है।

केंद्र सरकार: पहले तीन वर्षों के लिए आरसीएस हवाई अड्डों पर खरीदे जाने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क 2% तक सीमित किया गया है। एयरलाइनों को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कोड-शेयरिंग समझौते करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

राज्य सरकारें: राज्यों ने दस वर्षों के लिए एटीएफ पर वैट को 1% या उससे कम करने तथा सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं और उपयोगिता सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाएं कम दरों पर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है।

इस सहयोग ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है, जहां एयरलाइन्स कंपनियां लंबे समय से उपेक्षा किए गए क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान करते हुए फल-फूल सकती हैं।

उड़ान योजना का विकास: प्रारंभ से विस्तार तक

2016 में अपनी शुरुआत के बाद से उड़ान योजना कई चरणों से गुज़री है। इनमें से प्रत्येक ने भारत के क्षेत्रीय हवाई संपर्क के दायरे और क्षेत्र का विस्तार किया है। नीचे मुख्य चरणों का सारांश दिया गया है:

उड़ान 1.0 (2017)

- **शुरुआत:** पहली उड़ान 27 अप्रैल, 2017 को (शिमला-दिल्ली) रवाना हुई।
- **कवरेज:** 5 एयरलाइन संचालकों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 मार्ग आवंटित किये गये; इनमें 36 नये हवाई अड्डे भी शामिल हैं।

उड़ान 2.0 (2018)

- इस योजना का विस्तार करके इसमें 73 कम जुड़ाव वाले और ऐसे क्षेत्र जिनसे जुड़ाव नहीं था उन हवाई अड्डों को शामिल किया गया।
- पहली बार हेलीपैड को भी उड़ान नेटवर्क से जोड़ा गया।

उड़ान 3.0 (2019)

- पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से पर्यटन मार्ग शुरू किए गए।
- जल हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए समुद्री विमान परिचालन को शामिल किया गया।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई मार्गों को इस योजना से जोड़ा गया।

उड़ान 4.0 (2020)

- पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवा पर अधिक जोर दिया गया।
- अक्टूबर, 2025 में उड़ान ने अपने 9वें वर्ष में इस योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं

क्षेत्रीय संपर्क के लिए प्रमुख नवाचार और आगे की राह

उड़ान यात्री कैफे: हवाई यात्रा को अधिक समावेशी बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर किफायती यात्री कैफे शुरू किए गए हैं जो किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराते हैं— 10 रुपये में चाय और 20 रुपये में समोसे।

समुद्री विमान सेवा का संचालन: क्षेत्रीय और दूरस्थ क्षेत्र को जोड़ने के लिए 22 अगस्त, 2024 को समुद्री विमान सेवा संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए जिसमें सुरक्षा, संरक्षा और परिचालन व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया। देशभर में 50 से अधिक चिन्हित जल निकायों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए उड़ान राउंड 5.5 शुरू किया गया है।

उड़ान पहल का नवीनीकरण: मूल योजना की सफलता के आधार पर नवीनीकरण का लक्ष्य 120 नए गंतव्यों को जोड़ना और अगले दशक में 4 करोड़ से अधिक यात्रियों के लिए किफायती हवाई यात्रा को सक्षम बनाना है। इसमें दूरदराज, पहाड़ी और आकांक्षी जिलों, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के लिए विशेष सहायता पर ध्यान दिया गया है।

कृषि उड़ान योजना: किसानों को सहायता प्रदान करने तथा कृषि-उत्पादों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिए बनाई गई कृषि उड़ान विशेष रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों से समय पर तथा लागत प्रभावी हवाई रसद की सुविधा प्रदान करती है। यह बहु-मंत्रालय योजना वर्तमान में 58 हवाई अड्डों को कवर करती है, जिसमें 25 प्राथमिकता वाले हवाई अड्डों तथा देशभर में 33 अन्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

हवाई अड्डा अवसंरचना विकास: सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास शामिल है। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा और क्षेत्रीय विकास की भविष्य की मांग को पूरा करना है।

उड़ान योजना: मुख्य बातें

- उड़ान योजना 21 अक्टूबर, 2016 को शुरू की गई थी; पहली उड़ान 27 अप्रैल, 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच संचालित हुई थी।
- 625 उड़ान मार्ग चालू किए गए हैं जो पूरे भारत में 90 हवाई अड्डों (2 जल हवाई अड्डों और 15 हेलीपोर्ट सहित) को जोड़ते हैं।
- उड़ान के अंतर्गत 1.49 करोड़ से अधिक यात्री किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं।
- भारत का हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 में 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में 159 हवाई अड्डों तक पहुंच गया, जो एक दशक में दोगुने से भी अधिक है।
- वंचित एवं दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में 4,023.37 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
- उड़ान ने क्षेत्रीय पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और व्यापार को मजबूत किया जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला।

निष्कर्ष

उड़ान एक नीति से कहीं अधिक है– यह एक परिवर्तनकारी आंदोलन है जिसने भारत में विमानन क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया है। भारत और इंडिया के बीच दूरी को समाप्त कर इस योजना ने लाखों लोगों के लिए सस्ती हवाई यात्रा के सपने को साकार किया है। इसने न केवल दूरदराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर ला दिया है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा दिया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है और पूरे देश में रोजगार का सृजन किया है। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक विमानन केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, उड़ान समावेशी विकास, लचीलेपन और दूरदर्शी शासन का प्रतीक है। यह एक समय में एक उड़ान के साथ नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करती है। ■

'विश्व का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम सबसे कमजोर लोगों की कितनी अच्छी तरह देखभाल करते हैं'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 मई को जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 78वें सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को हार्दिक बधाई दी, इस वर्ष की थीम 'वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ' पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भारत के विजन के अनुरूप है। श्री मोदी ने 2023 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अपने संबोधन को याद किया, जहां उन्होंने 'वन अर्थ, वन हेल्थ' के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ दुनिया का भविष्य समावेशन, एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोग पर निर्भर करता है।

श्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि समावेशन भारत के स्वास्थ्य सुधारों के मूल में है, जो 580 मिलियन लोगों को कवर करती है और मुफ्त उपचार प्रदान करती है। इस कार्यक्रम को हाल ही में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। उन्होंने भारत के हजारों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के व्यापक नेटवर्क के बारे में बताया, जो कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच करने के साथ-साथ इनका पता लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं। श्री मोदी ने हजारों सार्वजनिक फार्मेसियों की भूमिका के बारे में भी बताया, जो काफी कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करती हैं।

श्री मोदी ने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण को ट्रैक करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूनिक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी सिस्टम जैसी भारत की डिजिटल पहलों से अवगत कराया, जो लाभों, बीमा, रिकॉर्ड और सूचना को एकीकृत करने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के साथ कोई भी मरीज अपने डॉक्टर से बहुत दूर नहीं है। श्री मोदी ने भारत की मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा पर प्रकाश डाला, जिसने 340 मिलियन से अधिक परामर्शों को सक्षम किया है।

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में उल्लेखनीय गिरावट

भारत की स्वास्थ्य संबंधी पहलों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "दुनिया का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम सबसे कमजोर लोगों की कितनी अच्छी तरह देखभाल करते हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का विजन अनुकरणीय, मापनयोग्य और टिकाऊ मॉडल प्रदान करता है। श्री मोदी ने दुनिया के साथ, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के साथ अपने ज्ञान और सर्वोत्तम प्रणालियों को साझा करने की भारत की इच्छा व्यक्त की।

भारत की स्वास्थ्य संबंधी पहलों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है

जून में 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस वर्ष की थीम, 'योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ' पर प्रकाश डाला और योग के जन्मस्थान के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देते हुए सभी देशों को आमंत्रित किया।

श्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और सभी सदस्य देशों को आईएनबी संधि की सफल वार्ता के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे भविष्य में होने वाली महामारियों से लड़ने के लिए अधिक वैश्विक सहयोग के माध्यम से साझा प्रतिबद्धता के रूप में वर्णित किया। श्री मोदी ने एक स्वस्थ धरती के निर्माण को महत्वपूर्ण बताने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया कि कोई भी पीछे न छूटे। ■

'ऑपरेशन सिंदूर' ने दुनिया-भर में आतंक के खिलाफ़ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है: नरेन्द्र मोदी

हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया, यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी–भारत में बने हथियारों, उपकरणों और तकनीक की ताकत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मई को मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 122वीं कड़ी की शुरुआत करते हुए कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस Precision के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। 'ऑपरेशन सिंदूर' ने दुनिया-भर में आतंक के खिलाफ़ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस Precision के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है

उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देश-भक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे-छोटे कस्बों में, तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन-अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वालंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए और हमने देखा चंडीगढ़ के वीडियोज तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थीं, संकल्प गीत गाये जा रहे थे। छोटे-छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े सन्देश छुपे थे।

श्री मोदी ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम 'सिंदूर' रखा गया है।

उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया, यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी—भारत में बने हथियारों, उपकरणों और तकनीक की ताकत। उसमें 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स हमारे तकनीशियन हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है।

'योग दिवस' को लेकर दुनिया-भर में जोश और उत्साह

श्री मोदी ने कहा कि 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। यह अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से जुड़ें। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। 21 जून, 2015 में 'योग दिवस' की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इस बार भी 'योग दिवस' को लेकर दुनिया-भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अलग-अलग संस्थान अपनी तैयारियां साझा कर रहे हैं। बीते वर्षों की तस्वीरों ने बहुत प्रेरित किया है। हमने देखा है अलग-अलग देशों में किसी साल लोगों ने योग चेन बनाई, योग रिंग बनाई। ऐसी बहुत ही तस्वीरें हैं जहां एक साथ चार पीढ़ी मिलकर योग कर रही हैं। बहुत से लोगों ने अपने शहर के प्रतिष्ठित स्थानों को योग के लिए चुना। आप भी इस बार कुछ रुचिकर तरीके से योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकते हैं।

योग में बढ़ती कॉरपोरेट भागीदारी की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे कॉरपोरेट भी इसमें पीछे नहीं हैं। कुछ संस्थानों ने अपने कार्यालयों में योग अभ्यास के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया है। कुछ स्टार्ट-अप ने कार्यालय में योग का समय तय किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो गांवों में जाकर योग सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोगों की ये जागरूकता मुझे बहुत आनंद देती है।

श्री मोदी ने कहा कि 'योग दिवस' के साथ-साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। उन्होंने कहा कि कल ही यानी 24 मई को डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक और मेरे मित्र तुलसी भाई की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन के तहत एक समर्पित पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को वैज्ञानिक तरीके से दुनिया भर में अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ■

एनडीए ने असम पंचायत चुनावों में शानदार जीत हासिल की

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने असम पंचायत चुनावों 2025 में शानदार जीत हासिल की, जिससे प्रदेश में उसकी राजनीतिक उपस्थिति और मजबूत हुई है।

एनडीए गठबंधन ने जिला परिषद् की 376 सीटों में से 300 सीटें जीतीं और 76 प्रतिशत से ज्यादा मत-प्रतिशत हासिल किया। यह जबरदस्त जीत न केवल गठबंधन को मिलने वाले व्यापक जमीनी समर्थन को दर्शाती है, बल्कि इसके शासन मॉडल में मतदाताओं के बढ़ते भरोसे को भी रेखांकित करती है। एनडीए गठबंधन ने आंचलिक पंचायत चुनावों में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया और प्रदेश की 2,192 सीटों में से 1,436 सीटों पर जीत हासिल की। इन स्थानीय निकायों में गठबंधन को 66 प्रतिशत मत हासिल हुआ। इसी के साथ एनडीए ने गांव और ब्लॉक स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस शानदार जीत के लिए असम की जनता को बधाई देते हुए कहा, "एनडीए के विकास केंद्रित एजेंडे को स्पष्ट समर्थन देने के लिए असम की जनता का आभार। असम की प्रगति के लिए हमारे प्रयास पूरे जोश के साथ जारी रहेंगे। मैं सभी एनडीए कार्यकर्ताओं की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने लोगों के बीच काम किया और हमारे विकास के एजेंडे को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया।"

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने असम की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "असम पंचायत चुनाव 2025 में एनडीए पर भरोसा जताने के लिए असम की जनता का हृदय से आभार। यह जनादेश विकासोन्मुखी नीतियों में लोगों के विश्वास और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में असम में हो रही उल्लेखनीय प्रगति का प्रमाण है। मैं इस जीत को सुनिश्चित करने में उनके असाधारण योगदान के लिए मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री दिलीप सैकिया जी और सभी समर्पित असम, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।"

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक पोस्ट में कहा, "पंचायत चुनाव 2025 में एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए असम की जनता का आभार। यह जीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की जन-केंद्रित नीतियों का अनुमोदन है, जिसने असम में शांति एवं समृद्धि के एक नये युग की शुरुआत की है। मोदी जी के विकास के संदेश को घर-घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा जी, असम भाजपा अध्यक्ष श्री दिलीप सैकिया जी और असम, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मेरी हार्दिक बधाई। हम सब मिलकर सभी के लिए एक 'विकसित असम' का निर्माण करेंगे।" ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

भुज (गुजरात) में 26 मई, 2025 को विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गांधीनगर (गुजरात) में 27 मई, 2025 को एक रोड शो के दौरान जन–अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 23 मई, 2025 को राइजिंग नॉर्थ–ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बीकानेर (राजस्थान) में 22 मई, 2025 को विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 24 मई, 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान एक समूहचित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 05 जून, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2025-27
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

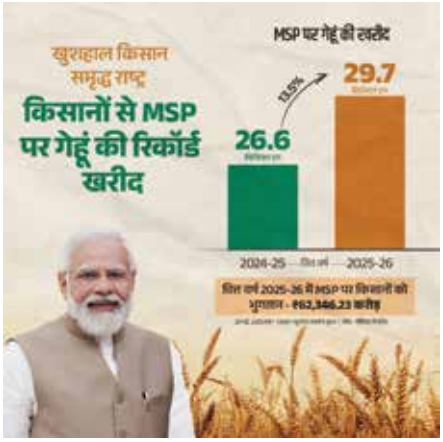

छायाकार: अजय कुमार सिंह